दैनिक
सनातन वीर
Reg. No. MPHIN/25A3002
राष्ट्रहित, धर्मरक्षा जनसेवा को समर्पित
नगर संस्करण | इंदौर, रविवार, 29 मार्च 2026 | वर्ष : 01, अंक : 114, कीमत : 03 रुपए, पृष्ठ : 8

डॉलर के सामने रुपया ढहा...

'45 से 94.82 तक गिरावट, महंगाई और पश्चिम एशिया संकट का असर'

नई दिल्ली ● एजेंसी

साल 2010 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 45 रुपये हुआ करती थी, जो मार्च 2026 में गिरकर 94.82 रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। पिछले डेढ़ दशक में डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 109% की गिरावट आई है, जो औसतन 4.7% सालाना की दर से है। एक निवेशक और आम नागरिक के तौर पर यह समझना जरूरी है कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारतीय मुद्रा लगातार दबाव में क्यों है।

इसका सबसे बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच लगातार बना रहने वाला महंगाई का अंतर है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई ऐतिहासिक रूप से 5-6% के बीच रही है, जबकि अमेरिका में यह अमूमन 2% के आसपास रहती है। जब भारत में कीमतें अमेरिका की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं, तो रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए रुपये का नाममात्र अवमूल्यन (मूल्य घटना) जरूरी हो जाता है।

मार्च 2026 में पश्चिम एशिया (विशेषकर ईरान) में युद्ध की स्थिति के कारण कच्चे तेल की कीमतें 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, इस हालात ने भारत के आयात बिल को असहनीय स्तर तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही, वैश्विक जोखिम बढ़ने पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफआईआई व एफपीआई) ने सुरक्षित निवेश (डॉलर और सोना) में निवेश के लिए भारतीय इक्विटी और ऋण बाजारों से 11 बिलियन डॉलर से अधिक की भारी निकासी की। वहीं, जनवरी 2026 में भारत में सोने के आयात में भी 349% का भारी उछाल भी देखा गया था। इन कारकों ने बाजार में डॉलर की मांग को अचानक बढ़ा दिया, इससे रुपया 94.82 के निचले स्तर पर आ गया। शुक्रवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 94.18 पर खुला और पहली बार 94.50 का स्तर पार करते हुए आखिरकार 89 पैसे की भारी गिरावट के साथ 94.85 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को यह 93.96 पर बंद हुआ था।

भारत का व्यापार घाटा रुपये के मूल्य पर दबाव डालने वाला एक निरंतर कारक है। जनवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा 34.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और फरवरी 2026 में यह 27.10 बिलियन डॉलर रहा। इसके अलावा, 2025 में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के चयनात्मक

टैरिफ ने नया भू-राजनीतिक जोखिम पैदा किया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, रुपया इन ऊंचे-ऊंचे टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में काम कर रहा है, ताकि भारतीय सामान वैश्विक बाजार में सस्ते रहें और निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहे।

फरवरी 2026 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिससे फेड फंड दर 4.75%-5.00% के दायरे में आ गई, जबकि RBI ने अपनी रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी है। यह संकुचित होता ब्याज दर अंतर विदेशी निवेशकों के लिए 'कैरी ट्रेड' के आकर्षण को कम करता है। इसके अलावा, भारत में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर आमतौर पर 10-12% रहती है, जो अमेरिकी मनी सप्लाई (5% के आसपास) वृद्धि से अधिक है, जो लंबे में रुपये पर दबाव डालता है।

भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई रुपये में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए समय-समय पर हस्तक्षेप करता है। हाल-फिलहाल मार्च 2026 तक उपलब्ध लगभग 723 अरब डॉलर के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग इसके लिए किया गया है। इससे बीते कुछ हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दिखी है। मार्च के पहले सप्ताह में युद्ध संकट के दौरान आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में सीधे तौर पर लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर बेचे थे। इसके साथ ही आरबीआई अपतटीय (देश के बाहर) एनडीएफ बाजार और प्री-मार्केट में भी डॉलर बेचकर सट्टेबाजों से रुपये को बचाने की जुगत लगाता है।

बिल्कुल नहीं। रुपये का किसी भी मुद्रा के साथ विनिमय दर केवल एक व्यापारिक संतुलन का उपकरण है। उदाहरण के लिए, जापानी येन डॉलर के मुकाबले पिछले एक दशक में बहुत अधिक कमजोर हुआ हुआ है, फिर भी जापान अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ईरान भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। बीते एक दशक में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं टिकती। हालांकि आज जब ईरान और अमेरिका आमने-सामने हैं, ईरान अपनी कमजोर मुद्रा के बावजूद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सामने तन कर खड़ा है। रुपये का 94.82 के स्तर तक गिरना घरेलू मुद्रा में कमजोरी के बजाय वैश्विक डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक कारणों से है और इससे भारत की 8.2% की शानदार जीडीपी वृद्धि दर पर कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ता फिलहाल नहीं दिखता। हालांकि, अर्थव्यवस्था को चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना समय-समय पर जरूर करना पड़ेगा।

देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी

युद्ध के संकट मे एकजुट होकर लड़ना है

नई दिल्ली ● एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया। 4 फेज पूरे होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल-अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा- कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। मैं देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है।

देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। यहां से हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। इसके चलते कई देशों में संकट पैदा हो गया है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों और किसानों पर बोझ न पड़े। 140 करोड़ देशवासी इस मुसीबत का एकजुट होकर सामना करें।

नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। जब यहां सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया। तब पुराने मुख्यमंत्री (अखिलेश) इतने डरे हुए थे कि वे कार्यक्रम में आए ही नहीं। मुझे भी डराने की कोशिश की गई। कहा गया- नोएडा मत जाइए। अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हैं।

सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, निर्माण हुआ और अब शुरू भी हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकट का मिलकर सामना करें। युद्ध हो रहा है। इसका सामना कैसे करें ये संसद में बताया है। देश के सभी सीएम से हमारी चर्चा हुई है।

रूस मे प्रेट्रोल के निर्यात पर प्रतिबन्ध भारत पर कम चीन तुर्की ब्राजील पर संकट

मॉस्को ● एजेंसी

रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए है।

नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल-ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन, तुर्किये, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वह पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने शुक्रवार को देश में पेट्रोल और दूसरे तेल उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति की समीक्षा की। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने शुक्रवार को देश में पेट्रोल और दूसरे तेल उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति की समीक्षा की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधेतौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) पर निर्भर है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से लगभग 20% रूस से आता है।

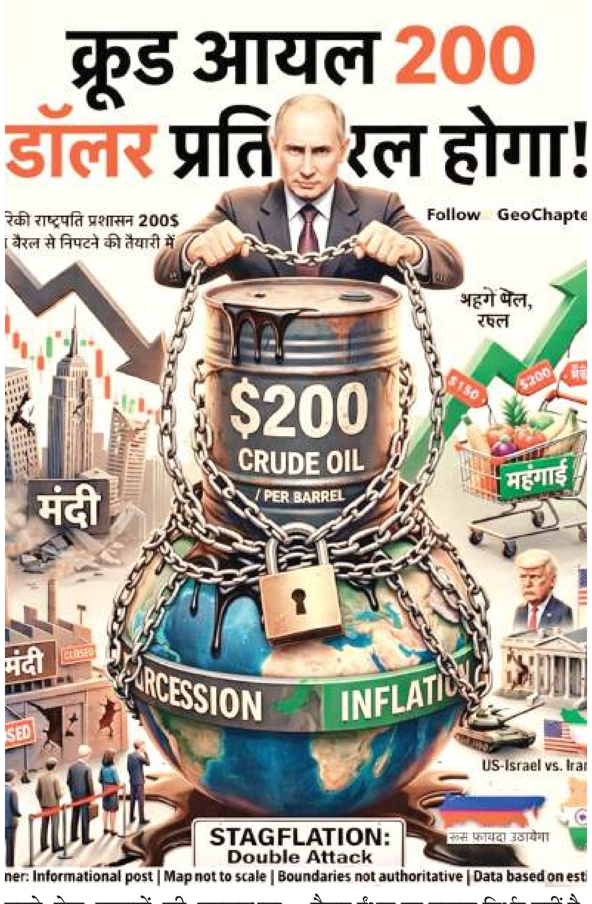

भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। इसके बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है। यही वजह है कि रूस के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। यह न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि रूस के फैसले से अगर वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। पहले से ही जंग के कारण तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। मॉस्को में शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर बैठक हुई थी। इसमें खासतौर पर यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ईंधन कीमतें नियंत्रित रखना चाहते हैं।

मंत्री नोवाक ने बैठक में कहा कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

बंगाल चुनाव आये और ममता का विक्टिम कार्ड बाहर निकला, कभी पैर कभी सर पर पट्टी

नई दिल्ली ● एजेंसी

गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी (असम) में रोड शो किया। इसके पहले शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया। शाह ने कहा, 'इसमें TMC सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है, ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है।'

उन्होंने कहा, 'ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं।' मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ममता के सिर में चोट में लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले उनके पैर में चोट लगी थी। उधर, TMC ने भी भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया।

अमित शाह ने गुवाहाटी में रोड शो किया। तमिलनाडु में DMK ने पार्टी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। इसके पहले पार्टी ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फाइलन की।

अयोध्या के राजघाट में हो रहे महायज्ञ में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

अयोध्या ● एजेंसी

अयोध्या के राजघाट में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शनिवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई जिससे अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि यज्ञ में नारियल फटने से चिंगारी निकली और आग लग गई। गनीमत रही कि घटना से कुछ ही मिनट पहले करीब 4500 श्रद्धालु यज्ञ में पूर्णाहुति देकर बाहर निकल चुके थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, स्वामी जी महाराज के द्वारा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कराया जा रहा था तभी हादसा हो गया। मौके पर दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। यज्ञ मंडप की आग पास की गोशाला तक पहुंच गई थी, लेकिन समय रहते गायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंच गई थीं, जिससे स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया। किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है।

इंदौर निगम की चालानी कार्रवाई पर भड़के व्यापारी

पाटनीपुरा-परदेशीपुरा की दुकानों में जबरन वसूली का आरोप, दुकानें बंद, अमले को रोकनी पड़ी कार्रवाई

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर में नगर निगम की चालानी कार्रवाई को लेकर शनिवार पाटनीपुरा-परदेशीपुरा क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। इंदौर नगर निगम की टीम के खिलाफ नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर रास्ता जाम कर दिया और विरोध स्वरूप दुकानें बंद कर दीं। घटना शाम करीब 4 बजे की है।

व्यापारियों का आरोप है कि निगम कर्मचारी चालानी कार्रवाई के नाम पर आए दिन क्षेत्र में पहुंचते हैं और दुकानों में घुसकर जबरन वसूली करते हैं। उनका कहना है कि बिना ठोस कारण के चालान काटे जाते हैं तथा अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। इस कथित मनमानी के विरोध में शनिवार को सभी व्यापारी एकजुट हो गए।

प्रदर्शन के दौरान व्यापारी सड़क पर आ गए जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हालात बिगड़ते देख निगम अमले को अपनी गाड़ियां छोड़कर पीछे हटना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि चालानी कार्रवाई के नाम वसूली बंद नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। दरअसल, शाम करीब साढ़े चार बजे निगम का रिमूवल दल मोबाइल कोर्ट के माध्यम से क्षेत्र में अतिक्रमण और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान कुछ व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जो धीरे-धीरे उग्र प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने निगम अधिकारियों पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कार्रवाई के नाम पर पैसे की मांग की जाती है। वहीं कुछ व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की कोशिश की गई। दूसरी ओर, निगम के रिमूवल दल के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने ही बाधा उत्पन्न की और टीम के साथ अभद्रता की गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंच संभाली स्थिति

स्थिति बिगड़ने पर परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका, बता दें की इंदौर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण और अन्य नियमों के उल्लंघन पर नियमित रूप से चालानी कार्रवाई की जाती है। हालांकि, इन कार्रवाइयों को लेकर समय-समय पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी सामने आते रहे हैं।

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जमी गंदगी

सिर, चेहरे से लेकर पूरी प्रतिमा पर गंदगी का अंबार; स्वच्छ शहर की पहचान पर दाग

इंदौर ● संवाददाता

शहर के हृदय स्थल में अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता स्व. महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा इन दिनों उपेक्षा और बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की कथित बेरुखी के चलते प्रतिमा का नियमित रखरखाव नहीं हो पा रहा है।

दशकों पूर्व शहर के मध्य स्थापित यह प्रतिमा आज कबूतरों की गंदगी से ढंकी नजर आ रही है। गांधीजी के सिर, चेहरे और गर्दन सहित पूरी प्रतिमा पर कबूतरों की बीट जमी हुई है। अभी जिस हालात में प्रतिमा है उससे लगता है कि लंबे समय से प्रतिमा की न तो धुलाई हुई है और न ही समुचित सफाई। शहर को स्वच्छता में देशभर में पहचान दिलाने

वाला इंदौर, अपने ही प्रमुख प्रतीक स्थल की उपेक्षा करता दिखाई दे रहा है। प्रतिमा के आसपास पक्षियों की मौजूदगी से भले वातावरण शांत लगता हो, लेकिन राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर जमी गंदगी शहर की प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल खड़े कर रही है। अभी नगर निगम तत्काल प्रभाव से प्रतिमा की सफाई, नियमित मेंटेनेंस और संरक्षण के ठोस इंतजाम करने की जरूरत है कि ताकि शहर के इस महत्वपूर्ण स्मारक की गरिमा बनी रह सके लेकिन जिम्मेदारों ने इस मुद्दे की सुध नहीं ली है। दरअसल यहां सैकड़ों की तादाद में कबूतर हैं। शहर के बीचों-बीच यहां सुबह-शाम पक्षी प्रेमी कबूतरों को दाने डालते हैं। इसके चलते उनकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। खुद सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर निगम द्वारा यहां बगीचे में पौधों और कबूतरों को पानी दिया जाता है लेकिन प्रतिमा की अनदेखी की जा रही है।

महिला पर कार चढ़ाने वाला पहले भी पकड़ा जा चुका

कार में लाल बत्ती लगाकर घूमते हुए पकड़ाया था; मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्रवाई हुई थी

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के शिव वाटिका टाउनशिप में इंजीनियर महिला पर कार चढ़ाकर मौत के घाट उतारने वाले पिता-पुत्र से पुलिस की पूछताछ जारी है। इस मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है कि आरोपी बेटा तीन महीने पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। दिसंबर माह में ही पुलिस ने उसे पकड़ा था और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की थी।

दरअसल, पुलिस ने उसे कार पर लाल बत्ती लगाकर घूमते हुए पकड़ा था। तब पुलिस ने उसके पिता को भी थाने बुलाया था और दोनों को समझाइश देते हुए कार्रवाई भी की थी। लसूडिया टीआई तारेश सोनी ने बताया कि आरोपी कुलदीप और मोहनीश दो दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। दिसंबर महीने में एंडेवर कार में लाल बत्ती लगाकर वह घूम रहा था। तभी मोहनीश को बीट 78 ने रोका था और उसे पकड़कर थाने लेकर आए थे। उस वक्त वह नाबालिग था, इस वजह से उसके पिता को भी थाने बुलवाया गया था। दोनों को मामले में समझाइश दी गई थी और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई थी।

बेटे ने कार से महिला कर्मचारी और शंपा पांडे को रौंदा था

शिव वाटिका टाउनशिप की सागर श्री एन्क्लेव में कुलदीप चौधरी ने अपना पेंटहाउस Airbnb को किराए

पर दे रखा है। यहां रोज नए लोग आते थे। इस बात को लेकर रहवासियों को आपत्ति थी, जिसे लेकर विवाद हो गया था। बुधवार को रहवासियों ने उनके फ्लैट की लाइट बंद कर दी थी। यह देखकर कुलदीप चौधरी नीचे आया और उसने रहवासियों के फ्लैट की लाइट बंद कर दी। इस बात को लेकर मारपीट हुई। इसके बाद बेटा मोहित उर्फ मोहनीश चौधरी कार लेकर आया। पहले वहां रहने वाली महिला कर्मचारी और फिर शंपा पांडे को टक्कर मार दी। शंपा को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पूरी वारदात बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो दो दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस पेंटहाउस की वैधता के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।

बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग ने किया सुसाइड

सिरपुर तालाब में मिली लाश, सुसाइड नोट में लिखा- 'मैं बीमारी से परेशान हो गया हूं'

इंदौर ● संवाददाता

हार्ट की बीमारी से तंग आकर एक बुजुर्ग ने सिरपुर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को बुजुर्ग के पास से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें बीमारी के कारण परेशान होने की बात लिखी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शनिवार को जिला अस्पताल में पीएम करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदन नगर टीआई तिलक करोले ने बताया कि मृतक का नाम मनोज (62) पिता राजाराम जायसवाल निवासी छोटा बांगड़दा है। शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी कि सिरपुर तालाब के पास किसी व्यक्ति के कपड़े और अन्य सामान पड़ा है। इस पर टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो सिरपुर तालाब में मनोज का शव मिला, जिसके बाद शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा। शनिवार को उनका पीएम करवाया गया है।

परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी, सुसाइड नोट मिला टीआई ने बताया कि बुजुर्ग लापता हो गए थे, जिसके चलते परिवार के लोगों ने एरोड्रम थाने में शुक्रवार को उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस को मृतक का लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं बीमारी से परेशान हो चुका हूं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

परिवार के लोग कर रहे थे तलाश मनोज के बेटे गणेश जायसवाल ने बताया कि वे दोपहर दो बजे से घर से लापता हो गए थे। रात को 1 बजे के करीब उनकी लाश मिली सिरपुर तालाब में। पिता के लापता होने के बाद हम उनकी तलाश कर रहे थे। आसपास और रिश्तेदारों में भी पता किया था, लेकिन उनका पता नहीं चला था। बाद में उनकी लाश मिलने की जानकारी मिली। वे दिल की बीमारी से परेशान थे। वे हार्ट पेशेंट थे। परिवार में तीन बच्चे है। दो बेटे एक बेटी है। बताया जा रहा है कि एक बार पहले भी सिरपुर तालाब पर जा चुके थे। इसलिए परिवार के लोग उनकी तलाश के लिए वहां पहुंचे थे।

पटेल मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग

इंदौर ● संवाददाता

तेजाजी नगर मेन रोड पर बने पटेल मार्केट में शनिवार को एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई और पास में बने मेडिकल स्टोर और क्लिनिक को भी चपेट में ले लिया। धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा था। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गए। सूचना पर तेजाजी नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 30 हजार लीटर पानी डालकर आग को बुझाया जा सका। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी हैं। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार की है। पटेल मार्केट में आग लगने की सूचना 11.21 पर कंट्रोल रूम से मिली थी। सूचना मिलने के तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके लिए रवाना हो गई थी।

हाईटेक हो रही इंदौर ट्रैफिक पुलिस

टायर किलर-बैरियर से गाड़ियों को रोकने की ट्रेनिंग, जवानों ने लिया लाइव डेमो

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर ट्रैफिक पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है। मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर और टायर किलर जैसे इक्विपमेंट्स का लाइव डेमो पुलिस जवानों ने लिया और किसी भी परिस्थिति में गाड़ियों को कैसे रोका जा सके, इसकी खास ट्रेनिंग ली। अधिकारियों की मौजूदगी में शनिवार को यह ट्रेनिंग विजय नगर चौराहे पर हुई।

बता दें कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के पास मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर और टायर किलर मंगवाए गए हैं। अब पुलिस जवान इनका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, ताकि भारी गाड़ियों को समय रहते रोका जा सके। डीसीपी (ट्रैफिक प्रभारी) राजेश कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी में पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी गई।

आधुनिक संसाधनों से लैस हो रही ट्रैफिक पुलिस

मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर : यह एक ऐसा बैरियर है, जिसे सड़क पर तुरंत लगाया जा सकता है। यह तेज रफ्तार और भारी गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से रोकने में सक्षम है।

टायर किलर (स्पाइक बैरियर) : यह कीलों वाली एक पट्टी होती है। अगर कोई अपराधी या संदिग्ध गाड़ी पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुकती, तो यह गाड़ियों के टायर पंचर कर गाड़ी को रोक देती है।

हाई स्पीड वाहनों को नियंत्रित करने की विशेष ट्रेनिंग

इस प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य किसी संदिग्ध/अपराध में इस्तेमाल गाड़ी को सुरक्षित रूप से रोकना, हाई स्पीड गाड़ियों को नियंत्रित करना और आकस्मिक परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देना था। डेमो के दौरान मौजूद अधिकारियों ने पुलिस जवानों से कहा कि इनका इस्तेमाल सावधानी से, प्रशिक्षित तरीके से और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करें। इस प्रकार की नियमित ट्रेनिंग या प्रैक्टिस से ट्रैफिक पुलिस की कार्यकुशलता, तत्परता और आपात स्थितियों में कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बन सकेगी।

टारगेट पूरा करने के लिए बन गया आरोपी

सिम बेचने में मिलता था बोनस, अपने ही फोटो पर एक्टिवेट कर दिए 84 सिम कार्ड, बैतूल से गिरफ्तार

इंदौर ● संवाददाता

बोनस के लालच में एक युवक को आरोपी बना दिया। उसने टारगेट पूरा करने के लिए अपने ही फोटो पर 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए। क्राइम ब्रांच ने उसे बैतूल से दबोच लिया। उसने बोनस की लालच में वारदात करना कबूल किया है। आरोपी ने अपनी बहन और दोस्त के नाम का भी इस्तेमाल उनकी बिना जानकारी के किया।

दरअसल, राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में ऑपरेशन FACE के तहत एक ही व्यक्ति के चेहरे का इस्तेमाल कर फर्जी सिम एक्टिवेट करने वाले युवक व POS एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने एक टीम बनाई, जिसमें कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन के तहत 3 FACE आइडेंटिफाई किए जो इंदौर शहर से संबंधित थे। कार्रवाई में क्राइम ब्रांच इंदौर ने FACE 1 के आरोपी को शुक्रवार को बैतूल से गिरफ्तार किया, जिसने लगभग 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट किए। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि कार्रवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों से CAF और संबंधित जानकारी निकालने पर पता चला कि लगभग सभी सिम कार्ड एक्टिवेशन में एक ही व्यक्ति के फोटो का इस्तेमाल किया गया। टीम बैतूल पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ाए युवक का नाम विपिन मगरदे है। कार्ड टारगेट पूरा करने के लिए दिया वारदात को अंजाम आरोपी से जब टीम ने पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। उसने ज्यादा बोनस कमाने की लालच में ये सिम एक्टिवेट की। आरोपी विपिन ने पूछताछ में बताया कि उसने विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए, जिसमें उसने अज्ञात व्यक्तियों के आधार कार्ड एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किए और POS एजेंटों के लिए उसने अपनी बहन और दोस्त के नाम का इस्तेमाल भी बिना उनकी जानकारी के किया।

विपिन, आरोपी

मुनिश्री आदित्य सागर ने दिए मानसिक और शारीरिक विकास के बीज मंत्र

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के नृसिंह वाटिका में आयोजित तीन दिवसीय 'मंत्राक्ष ध्यान शिविर' के दूसरे दिन शनिवार को साधना का अनूठा उत्साह देखने को मिला। परम पूज्य मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस शिविर में प्रातःकालीन सामूहिक मंत्र साधना के दौरान साधकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में हर वर्ग और हर आयु के साधकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

दूसरे दिन प्रवचन के दौरान मुनिश्री ने एक साधक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि "मंत्राक्ष के माध्यम से हम स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं।" उन्होंने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विशेष 'बीजाक्षर' प्रदान करते हुए बताया कि इन अक्षरों और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण एकाग्रता बढ़ाने के साथ-साथ शरीर की आंतरिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। शिविर में आयोजित विभिन्न सत्रों को लेकर विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। दिनभर चले अलग-अलग सत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं जिज्ञासु शामिल हुए। मंत्र साधना के साथ मुनिश्री ने जीवन प्रबंधन और तनाव मुक्ति के सरल सूत्र भी साझा किए, जिनसे साधक विशेष रूप से प्रभावित दिखाई दिए। तीन दिवसीय इस आध्यात्मिक महाकुंभ का समापन रविवार 29 मार्च को होगा। अंतिम दिन प्रातः 5:15 बजे से मंत्र और अक्षरों के संगम के माध्यम से आत्म-साधना की गहन यात्रा कराई जाएगी। साथ ही विशेष सत्रों में मंत्र दीक्षा एवं पूर्णाहुति की प्रमुख विधियां संपन्न की जाएंगी। जो साधक अब तक शिविर का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए रविवार अंतिम अवसर रहेगा।

संकल्प से समाधान अभियान : प्रशासन जनता के द्वार

उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन

एक ही मंच पर योजनाओं का लाभ और समस्याओं का समाधान

खरगोन ● संवाददाता

आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार "संकल्प से समाधान अभियान" के अंतर्गत 28 मार्च 2026 को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरगोन में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला प्रशासन के सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता रही, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

शिविर में राजस्व, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, खाद्य आपूर्ति सहित सभी प्रमुख विभागों के स्टाल लगाए गए। यहां नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरण भी किया गया, जिससे शिविर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। जनजागरूकता के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से योजनाओं, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विषयों पर प्रभावी संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर जांच एवं परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही किशोरियों एवं पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण भी किया गया, जिससे भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव का संदेश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियान के अंतर्गत 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 94,370 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। जिला स्तरीय शिविर के माध्यम से शेष लंबित प्रकरणों के समाधान की दिशा में भी ठोस कार्रवाई की गई।

मुख्य अतिथि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने अपने संबोधन में कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के साझा संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में यह स्पष्ट संकल्प लिया गया है कि 12 जनवरी से 31 मार्च की निर्धारित अवधि में कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो हितग्राही शेष रह जाएंगे, उन्हें भी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों पर नागरिक अपनी आवश्यकता अनुसार योजना का चयन कर पंजीयन करा सकते हैं, जिसके उपरांत पात्रता के अनुसार लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं एचपीवी टीकाकरण जैसे कार्यक्रम भविष्य की बीमारियों से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो गरीबी अपने आप दूर होगी।

कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कराया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाह से दूर रहकर अनिवार्य रूप से अपनी बालिकाओं का टीकाकरण कराएं। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बताया कि 01 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, अतः सभी पालक अपने बच्चों को प्रथम दिवस से ही नियमित रूप से स्कूल भेजें। विशेष रूप से ड्रॉपआउट विद्यार्थियों पर फोकस करते हुए उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया गया। उन्होंने कृषकों से ऑर्गेनिक कृषि अपनाने की अपील करते हुए कहा कि जिले में इसके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। साथ ही उद्धवन सिंचाई परियोजनाओं, गेहूं उपार्जन, सत्यापन एवं पंजीयन की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सभी कृषक बंधु ई-विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण की प्रक्रिया का लाभ लें, जिससे पारदर्शी एवं समयबद्ध सुविधा प्राप्त हो सके। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सभी उपस्थित जनों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साथ ही हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बंटी तंवर, नगर पालिका उपाध्यक्ष भोलू कर्मा, जिला पंचायत सीईओ मिलिंद कुमार नागदेवे, डिप्टी कलेक्टर अनिल जैन, लोकेश छापरे, एसडीएम वीरेंद्र कुमार कटारे सहित सभी जिला अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार शर्मा द्वारा किया गया एवं आभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश शाक्य द्वारा किया गया।

शिक्षकों के हित में लोकसभा में गूंजा मुद्दा, सांसद गजेंद्रसिंह पटेल ने TET नियमों पर पुनर्विचार की मांग उठाई

खरगोन/बड़वानी ● रविन्द्र परमार

खरगोन-बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश के शिक्षकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी।

सांसद पटेल ने सदन को अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में म. प्र राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किया गया है। जबकि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व नियमानुसार की गई थी, उस समय TET का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन NCTE के नियमों के अंतर्गत पूरी तरह वैध रूप से हुई थी और वे वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में TET को अनिवार्य किए जाने से उन्हें व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके मनोबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में TET की अनिवार्यता से राहत प्रदान करना न्यायसंगत और आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ पुनर्विचार कर शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लिया जाए, ताकि उनके अनुभव, सेवा और समर्पण का सम्मान बना रहे। उल्लेखनीय है कि इस विषय को विभिन्न जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है तथा शिक्षक संगठनों द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत कर इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है।

तलाकशुदा महिला से ग्वालियर के होटल में रेप

आरोपी एक साल तक शादी का झांसा देकर करता रहा शारीरिक शोषण

ग्वालियर ● संवाददाता

ग्वालियर में एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिचित युवक उसे शादी का झांसा देकर होटल ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

शिंदे की छावनी क्षेत्र में अपनी मां के साथ रहने वाली 35 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2011 में हुई थी, लेकिन 2013 में तलाक हो गया था। इसके बाद वह मायके में ही रह रही थी। करीब दो साल पहले एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात इंदरगंज थाना क्षेत्र के निर्धन नगर निवासी सुमित घुघे से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। युवती ने उसे अपने तलाक के बारे में बताया, जिस पर आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा और भरोसा दिलाया कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है। पीड़िता के अनुसार, 22 फरवरी 2025 को आरोपी उसे फूलबाग चौराहे के पास स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार उसे अलग-अलग मौकों पर होटल ले जाकर शारीरिक शोषण करता रहा।

7 साल के बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य

चॉकलेट का लालच देकर आरोपी ले गया, पुलिस ने दो घंटे में पकड़ा

अशोकनगर ● संवाददाता

अशोकनगर जिले के कचनार थाना क्षेत्र में एक 7 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्चे को अपने साथ ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया। बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बच्चे की मां उसे गांव के माता मंदिर में पूजा के लिए ले गई थी। मां मंदिर के अंदर पूजा कर रही थी, जबकि बच्चा बाहर खेल रहा था। पूजा के बाद जब मां बाहर आई तो बच्चा वहां नहीं मिला। थोड़ी देर बाद 7 वर्षीय बच्चा रोते हुए घर आया और उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। बच्चे ने बताया कि गांव का शिवचरण उसे चॉकलेट और पैसों का लालच देकर मंदिर के पीछे नाले में ले गया और वहां उसके साथ जबरन लैंगिक शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने इस गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए कचनार थाना प्रभारी पूनम सेलर को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

सर्वे भवन्तु सुखिन : कि कामना को लेकर मंदिर में हुए विभिन्न अनुष्ठान

बाघेश्वरी माता मंदिर में यज्ञ पूर्णाहूति के उपलक्ष्य में आयोजित किया भंडारा

खरगोन ● संवाददाता

ब्राह्मणपुरी स्थित श्री बाघेश्वरी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान गुरुवार को शुभ मुहूर्त में श्री गणेश पूजन, रुद्राभिषेक के साथ विभिन्न अनुष्ठानों एवं सप्तशती के पाठ के साथ शिव शक्ति हवन कर, शुक्रवार शाम को पूर्णाहुति की गई। पूर्णाहुति के पश्चात शनिवार को कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया। भंडारा संयोजक श्याम महाजन कालू ने बताया कि दोपहर 12.30 बजे से शुरू हुआ भंडारा शाम तक चलता रहा। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर पुजारी जगदीश ठक्कर ने बताया कि यह देव स्थान हमारे निजी आवास में स्थापित होकर प्रतिवर्ष चारों नवरात्रियो के साथ वर्ष की प्रथम नवरात्रि चेत्र नवरात्रि दुर्गा उत्सव के उपलक्ष्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः कि कामना को लेकर विभिन्न अनुष्ठान किए जाते है। लगातार 29 वर्षों से शिव शक्ति यज्ञ की पूर्णाहुर्ति के पश्चात भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि चैत्र दुर्गोत्सव के तहत ब्राह्मणपुरी स्थित श्री बाघेश्वरी माता मंदिर में नवरात्रि का पर्व बड़ी धुमधाम से मनाया जाता है। यहां गुड़ी पडवा से आरंभ होकर दुर्गा नवमी (श्री रामनवमी) तक विभिन्न अनुष्ठान आयोजित किए जाते है। इन अनुष्ठानों का शुक्रवार रामनवमी पर यज्ञ पश्चात समापन हुआ। भंडारा समिति ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले सभी भक्तों एवं दानदाताओं का सराहनीय योगदान रहा।

रामनवमी ड्यूटी के दौरान महंत और पुलिसकर्मी में विवाद

छतरपुर में ASI पर अभद्रता और जातिसूचक टिप्पणी के आरोप, SP ने जांच के निर्देश दिए

छतरपुर ● संवाददाता

छतरपुर में रामनवमी के अवसर पर यातायात व्यवस्था के दौरान एक महंत और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। संकट मोचन मंदिर के महंत राजीव लोचन दास ने सिविल लाइन थाने के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) पर अभद्रता और जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। इस घटना से जुड़े वीडियो शनिवार को सामने आए हैं।

रामनवमी कार्यक्रम के कारण शहर में यातायात मार्ग बदला गया था। महंत राजीव लोचन दास एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी पन्ना नाका के पास ASI ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिसकर्मी द्वारा ड्यूटी के तहत रोके जाने पर महंत नाराज हो गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। महंत राजीव लोचन दास का आरोप है कि ASI ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें अपमानित किया। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। एक अन्य वीडियो में महंत पुलिसकर्मी को नौकरी से हटवाने की बात कहते भी दिख रहे हैं। हालांकि, वायरल हुए वीडियो में पुलिसकर्मी महंत को केवल इशारा कर आगे जाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहा है। कथित अभद्र भाषा या जातिसूचक टिप्पणी का कोई स्पष्ट वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

2 बहनों को बंधक बनाकर रेप, एक ने बहलाया...दोस्तों को सौंपा

रतलाम में फैक्ट्री में किया दुष्कर्म, बोला- किसी को बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा

रतलाम ● संवाददाता

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अगरबत्ती फैक्ट्री में बंधक बनाकर दो बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक युवक उन्हें बहलाकर बाइक से वहां ले गया और अपने दो साथियों के हवाले कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें एक घर ले जाकर भी वारदात को अंजाम दिया। मामला नामली क्षेत्र का है।

घटना 25 मार्च की रात की है। शुक्रवार को परिजन के साथ नाबालिग और युवती थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राजवीर कुमावत, सुमित जाट और पवन जाट के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

कार्यक्रम से बहलाकर ले गया युवक

15 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वह अपनी चचेरी बहन के साथ एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में गई थी। रात करीब 9:30 बजे दोनों घर के बाहर बैठी थीं। इसी दौरान राजवीर कुमावत बाइक लेकर वहां पहुंचा। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह उससे 10 मिनट बात करना चाहता है और साथ चलने को कहा। इसके बाद वह दोनों को बाइक पर बैठाकर अगरबत्ती फैक्ट्री ले गया, जहां उसके दोनों साथी पहले से मौजूद थे। पीड़िता के अनुसार, वहां पहुंचने के बाद राजवीर उन्हें अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर चला गया। इसके बाद सुमित जाट उसे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।

वारदात के बाद जब बड़ी बहन बाहर निकली, तो उसकी चचेरी बहन मिली, जिसने बताया कि पवन जाट ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों को बाइक से एक घर ले जाया गया, जहां सुमित ने एक और पवन ने दूसरी युवती के साथ फिर दुष्कर्म किया।

60 फीट ऊंचाई से गिरा सुपरवाइजर, मौत, खिमला प्लांट में हादसे के बाद भड़के मजदूर, गाड़ियों से तोड़फोड़

नीमच। नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र स्थित खिमला पावर प्लांट में गुरुवार रात एक हादसे में एलएंडटी कंपनी के 25 वर्षीय सुपरवाइजर एहसान उल हक की मौत हो गई। यह घटना सुरक्षा इंतजामों में कमी को उजागर करती है। पश्चिम बंगाल निवासी एहसान प्लांट की करीब छह मंजिला ऊंची दीवार पर लोहे की प्लेट ठीक करने के लिए चढ़ा था। बताया गया है कि वहां सुरक्षा के लिए अनिवार्य सेफ्टी जाली नहीं थी, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद शुक्रवार को प्लांट परिसर में मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने काम बंद कर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरु कर दिया। आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी के ऑफिस में घुसकर हंगामा किया और फर्नीचर और कांच तोड़ दिए। मजदूरों की मुख्य मांग थी कि मृतक के परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। हंगामे की सूचना पर रामपुरा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को शांत कराया। रामपुरा थाना प्रभारी विपिन मसीह ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी एहसान उलशेख पिता रजीब शेख की मौत के बाद तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी। अभी कंपनी की ओर से तोड़फोड़ की शिकायत फिलहाल दर्ज नहीं कराई गई है।

भिंड में सड़क निर्माण में अनियमितता पर नाराजगी

रात में शुरु हुआ काम, गुणवत्ता पर उठे सवाल, लोगों ने की शिकायत

भिंड ● संवाददाता

भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 32 में सड़क निर्माण को लेकर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे मेला फाटक से मस्जिद तक बनाई जा रही सड़क पर अचानक रात के समय काम शुरू कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई।

जानकारी के अनुसार करीब 30 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य दो साल पहले स्वीकृत हुआ था। शुरुआती चरण में लेवलिंग और डामरीकरण किया जाना था, लेकिन निर्माण एजेंसी ने लापरवाही बरती। करीब 8 महीने पहले सड़क पर बोल्डर डालने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया था, जिससे लोग धूल और मिट्टी से परेशान थे। शनिवार को एजेंसी ने बिना सूचना के काम शुरू किया। पहले सड़क पर पानी डाला गया, फिर उसके ऊपर बिटुमिनस इमल्शन डालकर सतह को काला किया गया और उसके बाद जीरा गिट्टी बिछाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के ऊपर बिटुमिनस इमल्शन डालने से सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों का आरोप है कि काम के दौरान नगर पालिका का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। टाइम कीपर, उपयंत्री या सहायक यंत्री की अनुपस्थिति में काम किया गया, जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में नगर पालिका के उपयंत्री राजवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि यह पुराना कार्य है, जो 8-10 महीने पहले शुरू हुआ था। छुट्टी के दिन बिना सूचना के काम शुरू होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत मिली है और जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

मानवाधिकार आयोग ने वीआईटी यूनिवर्सिटी पर केस दर्ज किया

सीहोर में परिसर होने के बावजूद भोपाल नाम से प्रचार, छात्रों को भ्रमित करने की शिकायत पर कार्रवाई

सीहोर ● संवाददाता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीहोर जिले के कोठरी में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के खिलाफ शुक्रवार को एक प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा 'वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी' नाम से प्रचार करने की शिकायत पर की गई है, जबकि इसका परिसर भोपाल जिले में नहीं है।

विश्वविद्यालय का वास्तविक परिसर भोपाल शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सीहोर जिले की आष्टा तहसील में स्थित है। छात्रों को भ्रमित करने के लिए राजधानी भोपाल के नाम का उपयोग किया जा रहा था। इस संबंध में एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी।

छात्रों को भ्रमित करने का आरोप

एनएसयूआई ने अपनी शिकायत में बताया कि 'भोपाल' नाम के उपयोग से अन्य राज्यों के छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 'भोपाल' नाम देखकर कई विद्यार्थी यह मान लेते हैं कि संस्थान भोपाल शहर में है, जिससे बाद में उन्हें असुविधा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पूर्व में हिंसक प्रदर्शन हो चुका

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण पूर्व में छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त हुआ था, जिसने हिंसक घटना का रूप ले लिया था। छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी, अव्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता जैसे मुद्दे उठाए थे। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय परिसर में कथित अवैध क्लीनिक और अन्य अनियमितताओं के संबंध में भी पहले शिकायतें की जा चुकी हैं, जिन पर अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। इन सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने संबंधित पक्षों से प्रतिवेदन तलब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम छात्रों के अधिकारों और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

चिनार ड्रीम सिटी में लिफ्ट गिरने का मामला

उप समिति अध्यक्ष सहित दो सदस्यों पर लापरवाही बरतने पर केस दर्ज

भोपाल ● संवाददाता

भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित चिनार ड्रीम सिटी में 28 फरवरी को लिफ्ट गिरने से एक रहवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद उप समिति अध्यक्ष सहित दो सदस्यों पर लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक आई-605, चिनार ड्रीम सिटी मिसरोद निवासी अनुज पथरौल (24) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मंडीदीप में मार्केटिंग का काम करते हैं। बीते माह 28 फरवरी को वह अपने फ्लैट से अपने साथी प्रदीप यादव के साथ मंडीदीप फैक्ट्री में जाने के लिए निकले थे। सुबह 9.40 बजे पर अनुज पथरौल ने आई ब्लॉक की लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजा खुल गया और वह दोस्त प्रदीप के साथ लिफ्ट में चले गए। तभी अचानक लिफ्ट छठे फ्लोर से सीधे नीचे जाने लगी। अनुज ने इमरजेंसी बटन भी दबाया। लेकिन इसके बावजूद लिफ्ट नहीं रुकी और सीधे नीचे आकर गिर गई। इस हादसे में उनके दाहिने पैर की एंकल बोन फ्रेक्चर हो गया, जबकि साथी को मामूली चोट आई है।

तीन लोगों की लापरवाही आई सामने

प्राथमिक इलाज निजी अस्पताल में कराने के बाद वह अपने घर विदिशा चले गए। लिफ्ट गिरने के मामले

में उप समिति अध्यक्ष जयपाल शर्मा और लिफ्ट रिपेयर नीरज पवार सहित मेंटेनेंस प्रभारी प्रकाश विश्वकर्मा की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिसरोद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लापरवाही बरतने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

35,000 गैस सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग

रोज पौने 2 करोड़ के पेट्रोल-डीजल की सप्लाई, मंत्री बोले- बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक

भोपाल ● संवाददाता

मध्य प्रदेश में LPG और पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों के कारण लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। भोपाल में सिलेंडर की बुकिंग सामान्य से करीब 5 गुना तक बढ़ गई है। एक एजेंसी पर शुक्रवार को 1600 बुकिंग दर्ज हुईं, जबकि स्टॉक सिर्फ 350 सिलेंडर का था।

अन्य जिलों में भी इसी तरह के हालात सामने आए हैं। फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन के मुताबिक, लोग बुकिंग के तुरंत बाद एजेंसी या गोदाम पहुंच रहे हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि 2 से 4 दिन में सिलेंडर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल 32 से 35 हजार बुकिंग पेंडिंग हैं।

सरकार ने साफ किया गैस, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बॉटलिंग प्लांट और सप्लाई सिस्टम पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों की स्थिति बड़े शहरों में सामान्य है, लेकिन छोटे शहरों में अफवाह का असर ज्यादा दिख रहा है। कुछ जगहों पर पैनिक बाइंग के कारण बिक्री 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गई, जिससे अस्थायी रूप से लंबी लाइनें और स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बनी।

प्रदेश में रोजाना करीब 1.85 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की सप्लाई हो रही है। भोपाल के पास भौंरी स्थित डिपो से शहर के 192 पंपों को ईंधन मिलता है। राजधानी में हर दिन लगभग 12 लाख लीटर डीजल और 9 लाख लीटर पेट्रोल की आपूर्ति होती है और यहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

प्रदेश में अफवाह से बढ़ी बिक्री...भोपाल में आदेश जारी

अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ऐसे मामलों में एफआईआर के निर्देश दिए हैं। पिछले चार दिनों से पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ी है। कई शहरों में लोग सुबह से ही लाइन में लग रहे हैं, जबकि सरकार बार-बार स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। अब तक 2046 जगहों पर जांच की गई है और 2888 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नौ मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है।

भोपाल में गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई

घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच शनिवार को खाद्य विभाग ने भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों ने जवाहर चौक और घोड़ा नक्कास क्षेत्र में अवैध गैस सिलेडर रीफिलिंग पॉइंट और अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण स्थल पर छापा मारा। घोड़ा नक्कास क्षेत्र में लक्ष्मी टॉकीज गली में अल कैटरिंग और कैटरिंग के संचालक अब्दुल रहमान के निवास हाउस नंबर 9/8 खजूरी गली वार्ड 19 में गैस सिलेंडर की छान बिन की गई और घर में 28 (15 नग घरेलू प्रवर्ग के,9 नग व्यवसायिक प्रवर्ग तथा 4 नग 5 केजी के) गैस सिलेंडर, कैटरिंग दुकान में 30 नग गैस सिलेंडर (12 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 18 नग छोटे 5kg क्षमता के गैस सिलेंडर) का अवैध भंडारण पाया है। अवैध भंडार पाए जाने के कारण कैटरिंग संचालक से कुल 56 नग विभिन्न कंपनी और क्षमता के जब्त किए जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। जवाहर चौक स्थित ए 1 इलेक्ट्रिकल्स की जांच की गई। मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर से लोकल गैस सिलेंडर में पीतल बंसी का प्रयोग कर गैस का अंतरण पाया गया। मौके से दुकान संचालक शाहिद से 3 नग घरेलू सिलेंडर 1 नग लोकल गैस सिलेंडर 4 नग पीतल बंसी जब्ती की गई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त पूलबोगदा पर घरेलू प्रबल का गैस सिलेंडर भरा हुआ देने पर अधिक कीमत वसूलने पर सालिक कुरैशी को पाया गया। उसके खिलाफ कालाबाजारी किए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक जादौन ने बताया कि जिले में अलग-अलग टीमों के माध्यम से निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

उज्जैन में डिलीवरी होते ही चोरी हुआ सिलेंडर

उज्जैन जिले के नागदा में बदमाश घर में रखा गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना शुक्रवार को नागदा की राजीव कॉलोनी में रहने वाले अतीक अहमद के घर हुई। अतीक ने बताया कि दोपहर में परिवार के सदस्य घर के कामों में व्यस्त थे। उसी दिन सिलेंडर घर आया था। दोपहर करीब 1.30 बजे सिलेंडर घर पहुंचा, जिसे पहले कमरे में रखा गया था। इस दौरान घर के सभी सदस्य मकान की पहली मंजिल पर थे। मौका पाकर एक व्यक्ति सिलेंडर उठाकर बाइक पर ले गया। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। परिवार वालों को सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर दोपहर करीब 3.30 बजे इस घटना का पता चला। थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आदमपुर छावनी पठार से आई महिला ने बताया कि पिछली टंकी 30 दिन पहले ली थी। उसी समय बुकिंग कराई थी। गैस एजेंसी वाले कह रहे हैं कि अब अप्रैल के बाद गैस सिलेंडर मिलेगा।

टीईटी समेत 3 मांगों के लिए बनेगा संयुक्त मोर्चा

एमपी के 1.5 लाख शिक्षक सामूहिक बैठक में बनाएंगे आंदोलन की योजना

भोपाल ● संवाददाता

मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर टीचर्स विरोध का रास्ता अपनाने की तैयारी में है। वे इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। कल यानी 29 मार्च को प्रदेश भर के शिक्षकों की सामूहिक मीटिंग होने जा रही हैं।

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल के आदेश अनुसार ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी परीक्षा देनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उठाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षकों को आदेश जारी होने की तारीख से दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक तय समय सीमा में टीईटी पास नहीं करता है तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च को सभी जिलों से ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी मांगी है, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। इसको लेकर जारी नए आदेश के अनुसार, यह जानकारी 31 मार्च तक देने के निर्देश दिए गए हैं। यही विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि इस दायरे में वे शिक्षक भी आ रहे हैं, जो 2005 और 2008 की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए थे और उस समय लागू नियमों के अनुसार पात्र थे। अब नए नियम लागू होने की आशंका ने पूरे शिक्षा तंत्र में असंतोष पैदा कर दिया है।

शिक्षक बोले- आगे की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे

शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 29 मार्च को सभी शिक्षक संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई है। इस बैठक में संयुक्त शिक्षक मोर्चा बनाया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। टीईटी के अलावा "शिक्षक एप से अटेंडेंस" और "सेवा वृद्धि" जैसे मुद्दे भी प्रमुख रहेंगे। इस बैठक में ही शिक्षक आगे आंदोलन का प्लान तैयार करेंगे।

उज्जैन-चित्रकूट-काशी को जोड़कर बनेगा नया "टूरिज्म सर्किट'

31 मार्च को काशी में होगा एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन, सीएम होंगे शामिल

भोपाल ● संवाददाता

मध्यप्रदेश के धार्मिक पर्यटन को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 मार्च को वाराणसी (काशी) में एक बड़ा रोडमैप तैयार करेंगे।

31 मार्च को होने वाले 'एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026' का मुख्य केंद्र बिंदु धार्मिक पर्यटन और आधुनिक तीर्थ प्रबंधन होगा। मुख्यमंत्री का विजन है कि जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने यूपी के पर्यटन को बदला है, उसी तर्ज पर एमपी के पवित्र स्थलों का कायाकल्प किया जाए।

काशी-उज्जैन-चित्रकूट: बनेगा बड़ा 'धार्मिक सर्किट'

सम्मेलन में सबसे बड़ी घोषणा 'काशी-उज्जैन-चित्रकूट' टूरिज्म सर्किट को लेकर हो सकती है। सरकार का प्लान है कि इन तीनों पवित्र शहरों को एक ही रूट और पैकेज से जोड़ा जाए। इसके लिए टूर ऑपरेटर्स और IRCTC के साथ मिलकर एक साझा मॉडल तैयार किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु एक ही यात्रा में तीनों धामों के दर्शन सुगमता से कर सकें।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन करेंगे CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 31 मार्च

को अपनी यात्रा की शुरुआत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भ्रमण से करेंगे। यहां वे 'क्राउड मैनेजमेंट', इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई आधुनिक सुविधाओं का बारीकी से अध्ययन करेंगे। इस सफल मॉडल की तर्ज पर एमपी में भी तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी।

गंगा-नर्मदा क्राफ्ट कॉरिडोर की शुरुआत

पर्यटन के साथ-साथ रोजगार पर भी जोर रहेगा। 'जॉइंट आर्टिजन वर्कशॉप' में एमपी के चंदेरी-महेश्वरी शिल्पकार और बनारस के सिल्क कारीगर एक साथ आएंगे। 'गंगा-नर्मदा क्राफ्ट कॉरिडोर' के जरिए दोनों राज्यों के उत्पादों की साझा ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे स्थानीय कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सके।

एमपी-यूपी के बीच होंगे ऐतिहासिक समझौते

इस दौरान पर्यटन, निवेश और हस्तशिल्प को लेकर कई एमओयू (MoU) साइन किए जाएंगे। सम्मेलन में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें एमपी के प्रमुख पर्यटन स्थलों और ओडीओपी (ODOP) उत्पादों की ताकत दिखाई जाएगी।

MP में महावीर जयंती पर सरकारी छुट्टी को लेकर सस्पेंस

विधायकों की मांग 30 मार्च को अवकाश हो, मंथन में जुटी सरकार

भोपाल ● संवाददाता

मध्य प्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश को लेकर सस्पेंस है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की है। उधर, सरकार के पास कुछ ऐसे भी सुझाव आए हैं कि शासकीय अवकाश को यथावत 31 मार्च को ही रखा जाए। अब सरकार विचार-मंथन में जुटी हुई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस मामले में और सुझाव ले रहा है।

पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में महावीर जयंती के सरकारी अवकाश की तिथि में संशोधन करने का आग्रह किया है। विधायक ने मांग

की है कि प्रदेश में 31 मार्च 2026 के स्थान पर 30 मार्च 2026 को शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। कांग्रेस विधायक ने पत्र में उल्लेख किया है कि जैन धर्म की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक इस वर्ष 30 मार्च को मनाया जाएगा।

राजपत्र में संशोधन की मांग, हाईकोर्ट का दिया हवाला

विधायक ने बताया कि मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्तमान में 31 मार्च (मंगलवार) को छुट्टी घोषित की है, जिसे जनभावनाओं और धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए बदलने की आवश्यकता है। पत्र में यह भी तर्क दिया है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने भी अपनी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 30 मार्च को ही अवकाश घोषित किया है। विधायक ने पूर्व में होली के पर्व पर शासन द्वारा किए गए संशोधनों का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है।

बंडा से भाजपा विधायक ने भी लिखा लेटर

बंडा (सागर) विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार ने शासन को पत्र लिखकर आगामी 31 मार्च 2026 के स्थान पर 30 मार्च 2026 को शासकीय अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। विधायक का तर्क है कि जैन धर्म की मान्यताओं और पंचांग के अनुसार भगवान महावीर का जन्म कल्याणक देशभर में 30 मार्च (सोमवार) को मनाया जाएगा। ऐसे में 31 मार्च को सरकारी छुट्टी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। पत्र में जनभावनाओं और धार्मिक रीति-रिवाजों का हवाला देते हुए इसे 'आंशिक संशोधन' की श्रेणी में रखने की बात कही है।

इंडीमून्स आर्ट्स फेस्टिवल का आज तीसरा दिन : अभिनेता संजय मिश्रा करेंगे नाटक 'घासीराम कोतवाल' का मंचन

भोपाल ● संवाददाता

भोपाल के रवींद्र भवन में चल रहे इंडीमून्स फेस्टिवल के तीसरे दिन आज फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान वे मशहूर नाटक "घासीराम कोतवाल" का मंचन करेंगे, जिसे विजय तेंदुलकर ने लिखा है और इसका निर्देशन अभिजीत पनसे ने किया है। कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मिश्रा ने कहा कि भले ही आज लोग मोबाइल, वेब सीरीज और डॉक्यूड्रामा तक सीमित हो रहे हैं, लेकिन आर्ट फेस्टिवल आज भी लोगों को जोड़ने का मजबूत माध्यम हैं और उनकी अपनी अलग अहमियत बनी हुई है।

अभिनेता राजीव वर्मा भी उपस्थित रहेंगे-

आज के कार्यक्रम में दिग्गज अभिनेता राजीव वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में मलॉय जैन, मनोज नायर, अनूप जोशी और मॉडरेटर के रूप में सीमा रायजादा भी शामिल होंगे।

गलत इलाज से बिगड़ रहा एपीडी, 90% मरीज अनजान : डॉक्टर बोले- मरीज 'गैस' समझकर नजरअंदाज कर रहे बीमारी

भोपाल। भोपाल के अस्पतालों में हर दिन ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें महीनों से गले में जलन, खट्टे डकार और आवाज बैठने की समस्या है, लेकिन वे इसे साधारण एसिडिटी समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. यशवीर जेके के अनुसार, यह एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है, जो धीरे-धीरे गले को गंभीर नुकसान पहुंचा देता है। डॉ. यशवीर ने कहा कि चिंता की बात यह है कि करीब 90 प्रतिशत मरीज शुरुआत में गलत इलाज लेते हैं। वे अलग अलग विभागों में भटकते रहते हैं। वहीं, बदलती जीवनशैली के कारण यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है और अब यह हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। भोपाल के 42 वर्षीय एक निजी कर्मचारी पिछले 6 महीनों से सीने में जलन और गले में खराश की समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने इसे सामान्य गैस समझकर मेडिकल स्टोर से दवाएं लेना शुरू कर दिया। कुछ समय राहत मिली, लेकिन समस्या बढ़ती गई। बाद में जांच में सामने आया कि उन्हें एपीडी है और उनके गले में सूजन तक पहुंच चुकी है।

संपादकीय

आर्थिक बोझ के नाम पर अधिकार नहीं छीन सकते

देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि विकास योजनाओं और सार्वजनिक परियोजनाओं के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। जब भी किसी नागरिक की भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो उसके बदले उसे न्यायसंगत मुआवजा देना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इसी सिद्धांत को मजबूत करता है, जिसमें यह साफ कहा गया कि केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह मामला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह दलील दी थी कि मुआवजे और ब्याज का भुगतान करने से उस पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ेगा। इस आधार पर उसने पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। किंतु न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि आर्थिक बोझ का आकलन किसी भी स्थिति में न्यायसंगत मुआवजे की संवैधानिक गारंटी को कमजोर करने का आधार नहीं बन सकता।

न्यायालय की पीठ ने अपने निर्णय में यह रेखांकित किया कि जब राज्य या उसकी एजेंसियां किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करती हैं, तो वह व्यक्ति केवल अपनी भूमि ही नहीं खोता, बल्कि उसके साथ जुड़ी आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में मुआवजा केवल जमीन के मूल्य का भुगतान नहीं, बल्कि एक व्यापक न्यायिक प्रतिपूर्ति होती है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है ताकि देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में सभी भू-स्वामियों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कुछ मामलों में भू-स्वामियों ने न्यायालय या मध्यस्थता की प्रक्रिया का सहारा लेकर अधिक मुआवजा प्राप्त किया है, जबकि अन्य मामलों में अंतिम निर्णय हो चुका है। न्यायालय ने यह संतुलन बनाने की आवश्यकता बताई कि जहां एक ओर लोगों को उनका उचित अधिकार मिले, वहीं दूसरी ओर पहले से निपटाए गए मामलों में अनिश्चितता न उत्पन्न हो।

वास्तव में भूमि अधिग्रहण का विषय केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। भारत जैसे देश में, जहां बड़ी आबादी की आजीविका भूमि पर निर्भर है, वहां अधिग्रहण का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। ऐसे में मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि केवल इस आधार पर कि मुआवजा और ब्याज का भुगतान करने से बड़ी वित्तीय देनदारी उत्पन्न होगी, पुनर्विचार का कोई वैध आधार नहीं बनता। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि राज्य की वित्तीय स्थिति नागरिकों के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। यदि ऐसा होने लगे, तो यह संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और संरक्षण का अधिकार दिया गया है।

इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायसंगत मुआवजा केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। जब सरकार या उसकी एजेंसियां विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण करती हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित लोगों को उचित और पर्याप्त मुआवजा मिले, जिससे वे अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकें।

यह फैसला उन लाखों किसानों और भू-स्वामियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी जमीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है। इससे यह विश्वास मजबूत होता है कि न्यायालय उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी परिस्थिति में उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा।

साथ ही, यह निर्णय नीति-निर्माताओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल परियोजनाओं की गति और लागत को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन लोगों के हितों की भी रक्षा करनी होगी, जो इन परियोजनाओं से सीधे प्रभावित होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना

लेखक - किशन भावनानीं

भारत में धर्म परिवर्तन, अनुसूचित जाति आरक्षण -24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला -संवैधानिक सिद्धांत, न्यायिक व्याख्या और सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव का व्यापक विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 25 और कंस्टीटूशन (शेड्यूल्ड क़ास्ट्स) आर्डर,1950 में निहित हैं- कानून में बदलाव, सामाजिक जागरूकता और नीति सुधार जरूरी

वैश्विक स्तरपर भारत जैसे बहु- धार्मिक,बहु-सांस्कृतिक और बहु-जातीय समाज में धर्म, जाति और सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र रहा है। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा सुनाया गया ताजा फैसला इसी जटिल विमर्श को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। इस निर्णय में अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदू,सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्म विशेषकर ईसाई और इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण लाभ प्राप्त नहीं होंगे। यह निर्णय केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना,ऐतिहासिक अन्याय के प्रतिकार और आधुनिक सामाजिक संरचना के बीच संतुलन बनाने का प्रयास भी है। मैं एडवोकेट किशनसनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि इस निर्णय की जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और कंस्टीटूशन (शेड्यूल्ड क़ास्ट्स) आर्डर 1950 में निहित हैं। 1950 के इस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बाद में इसमें संशोधन कर सिख (1956) और बौद्ध (1990) धर्मों को भी शामिल किया गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम समुदायों को इस दायरे से बाहर रखा गया। अदालत ने अपने ताजा फैसले में इसी संवैधानिक ढांचे को पुनः पुष्ट करते हुए कहा कि धर्मांतरण के साथ ही व्यक्ति का एससी दर्जा तत्काल और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है।यह फैसला आंध्र प्रदेश से जुड़े एक मामले पर आधारित है, जिसमें चिंथाडा आनंद नामक व्यक्ति जो ईसाई पादरी थे,ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके साथ जातिगत भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए एफआईआर रद्द कर दी कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद आनंद का अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें इस कानून के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा, जिससे यह सिद्धांत और अधिक मजबूत हो गया कि धर्म परिवर्तन केवल आस्था का परिवर्तन नहीं, बल्कि कानूनी पहचान में भी बदलाव लाता है।यहां यह समझना आवश्यक है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें किसी भी धर्म को मानना,उसका पालन करना और उसका प्रचार करना शामिल है।लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है; इसके साथ कुछ सामाजिक और कानूनी परिणाम भी जुड़े होते हैं।अदालत ने अपने फैसले में इसी संतुलन को रेखांकित करते हुए कहा कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि उस विशेष सामाजिक और धार्मिक ढांचे में झेली गई ऐतिहासिक प्रताड़ना है।चूंकि जाति व्यवस्था मुख्यतः हिंदू सामाजिक संरचना से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए अन्य धर्मों में जाने पर उस विशेष प्रकार की सामाजिक पहचान स्वतः समाप्त हो जाती है।

साथियों बात अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक ढांचा इसको समझने की करें तो भारत में अनुसूचित जातियों की अवधारणा का मूल उद्देश्य उन समुदायों को विशेष संरक्षण देना था, जिन्होंने सदियों तक सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना किया। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस आदेश के अनुसार, प्रारंभ में केवल हिंदू धर्म के भीतर आने वाले दलित समुदायों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी इसमें शामिल किया गया।संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे किन समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करेंगे।वहीं अनुच्छेद 25प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकारों का टकराव उत्पन्न होता है एक ओर धर्म बदलने की स्वतंत्रता,दूसरी ओर सामाजिक न्याय की जबरदस्त सटीक नीतियां।

साथियों बात अगर हम 24 मार्च 2026 का निर्णयः कानूनी स्पष्टता या सामाजिक विवाद? इसको समझने की करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म परिवर्तन के साथ ही एससी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। अदालत ने कहा कि 1950 का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है और इसमें जिन धर्मों का उल्लेख नहीं है, उनमें जाने पर व्यक्ति एससी की श्रेणी से बाहर हो जाता है।इसका अर्थ यह है कि यदि कोई दलित ईसाई या मुस्लिम बनता है, तो वह एससी आरक्षण और एससी /एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का लाभ नहीं उठा सकता।यह निर्णय कानूनी रूप से स्पष्टता प्रदान करता है,लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह कई प्रश्न भी खड़े करता है।

साथियों बात अगर हम इस निर्णय के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को समझने की करें तो ये व्यापक हो सकते हैं। यदि भविष्य में नीति में बदलाव कर ईसाई और मुस्लिम दलितों को भी एससी आरक्षण में शामिल किया जाता है, तो इससे आरक्षण की वर्तमान संरचना पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे मौजूदा लाभार्थियों के हिस्से में कमी आ सकती है।इसके अलावा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरक्षित सीटों पर नए समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।दूसरी ओर,आलोचकों का यह भी तर्क है कि यदि धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण का लाभ जारी रखा जाता है, तो इससे धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, इस तर्क का विरोध करने वाले कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल आरक्षण के लिए धर्म नहीं बदलता; इसके पीछे सामाजिक सम्मान, भेदभाव से मुक्ति और बेहतर जीवन की तलाश जैसे गहरे कारण होते हैं। ऐसे में आरक्षण को धर्म से जोड़ना सामाजिक वास्तविकताओं की अनदेखी करना हो सकता है।

साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फसलों को समझने की करें तो (1)सूसाई बनाम भारत संघ (1986):सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले 1986 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय का कोई व्यक्ति यदि ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह अनुसूचित जाति के लिए बनी योजनाओं और लाभों के लिए पूरी तरह अयोग्य हो जाता है।सी. सेल्वाराणी मामला (2024): सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसले में कहा कि ईसाई धर्म अपनाने पर व्यक्ति अपनी मूल जाति खो देता है। अदालत ने कहा कि धर्मांतरण सच्ची आस्था से होना चाहिए। अगर धर्म परिवर्तन केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया गया है तो इसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह आरक्षण के सामाजिक उद्देश्य को खत्म करता है। अदालत ने दोहरी पहचान रखने को संविधान के साथ धोखा करार दिया था। (2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया फैसलाऐसा ही एक मामले में पिछले साल दिसंबर में फैसला आया था। जितेंद्र साहनी नाम के एक व्यक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया है, तो वह कानूनी रूप से एससी का दर्जा बरकरार नहीं रख सकता। अदालत ने 1950 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जो हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं है, वह एससी नहीं हो सकता। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए कि पूरे राज्य में ऐसे मामलों की जांच की जाए, जहां अल्पसंख्यक धर्मों में धर्मांतरित लोग अभी भी गैरकानूनी रूप से एससी वर्ग को मिलने वाले लाभों का दावा कर रहे हैं।(3)मद्रास उच्च न्यायालय में भी आए केससी. सेल्वाराणी मामला (2023): सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सी. सेल्वाराणी केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा था। यहां एक ऐसी महिला को एससी प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया था, जो जन्म से ईसाई थी और नियमित रूप से चर्च जाती थी, लेकिन केवल सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए खुद को हिंदू और वल्लुवन जाति का बता रही थी।अकबर अली मामलाः मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण के बाद व्यक्ति अपनी जाति को आगे नहीं ले जा सकता। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब कोई हिंदू इस्लाम अपना लेता है, तो वह केवल एक मुसलमान बन जाता है और मुस्लिम समाज में उसकी जगह इस बात से तय नहीं होती कि धर्मांतरण से पहले उसकी जाति क्या थी।(4) कर्नाटक हाईकोर्ट बोला था- ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ईसाइयों को एससी एक्ट के तहत संरक्षण देना गलत है। अदालत का मानना था कि यह कानून विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए बना है, जबकि ईसाई धर्मशास्त्र में जाति-व्यवस्था जैसी कोई प्रथा ही नहीं है।

साथियों बात कर हम अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस मुद्दे को समझने की करें तो भारत का यह मॉडल अद्वितीय है। अधिकांश देशों में सकारात्मक भेदभाव जाति के बजाय नस्ल, जातीयता या आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में अश्वेत और अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर दिए जाते हैं, लेकिन यह धर्म से नहीं जुड़ा होता। भारत में आरक्षण का आधार ऐतिहासिक जातिगत उत्पीड़न है, जो इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक अलग पहचान देता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि संतुलन की तलाश,धर्म परिवर्तन और आरक्षण का यह मुद्दा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय की आवश्यकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन यह बहस को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा करता है।

वैश्विक ऊर्जा संकट बनाम लॉकडाउन की आशंका?

लेखक - किशन सनमुखदास भावनानी

- क्या दुनियाँ फिर कोविड-19 जैसे दौर की ओर बढ़ रही है या यह केवल भय और अफवाहों का जाल है? क्या दुनियाँ एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है?- अफवाह बनाम ज़मीनी हकीक- भय,भ्रम और बदलती वैश्विक वास्तविकता पीएम की लगातार बैठकें,देश में तेल,गैस और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित करना -अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी को ध्यान में रखना ज़रूरी

वैश्विक स्तरपर कोविड -19 महामारी ने दुनियाँ को जिस तरह से झकझोर कर रख दिया था,उसकी स्मृतियाँ आज भी लोगों के मन में ताज़ा हैं। 2020-21 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन,आर्थिक गतिविधियों का ठप होना,सड़कों पर सन्नाटा और अनिश्चित भविष्य ये सब अनुभव आज भी समाज की सामूहिक चेतना में गहराई से बसे हुए हैं।ऐसे में जब 2026 में ऊर्जा संकट, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और सरकारों की लगातार बैठकों की खबरें सामने आती हैं,तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह सवाल उठता है,क्या दुनियाँ एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है? क्या यह एक नए प्रकार का ऊर्जा लॉकडाउन होगा? या यह केवल अफवाहों औरसोशल मीडिया की उपज है?मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं क़ि इस बार संकट का कारण कोई वायरस नहीं,बल्कि ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताएँ हैं।पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। कुछ देशों में बिजली की खपत कम करने के लिए स्कूल-कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है,सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में केवल चार दिन काम का मॉडल अपनाया जा रहा है, और वर्क फ्रॉम होम को फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है।यह स्थिति भले ही कोविड जैसी स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उतने ही गहरे हो सकते हैं।श्रीलंका जैसे देशों में पहले से ही ऊर्जा संकट के कारण सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि ऊर्जा संकट केवल आर्थिक समस्या नहीं है,बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और नागरिक जीवन को भी सीधे प्रभावित करता है।भारत की स्थिति की व्याख्या हम,सतर्कता लेकिन घबराहट नहीं के रूप में कर सकते हैं,भारत भी इस वैश्विक संकट को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 26 मार्च 2026 को शाम साढ़े छह बजे बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है।इन बैठकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में तेल,गैस और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के पास लगभग 60 दिनों का ईंधन भंडार उपलब्ध है, जो तत्काल किसी बड़े संकट की संभावना को कम करता है।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है।वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने संयुक्त रूप से बयान देकर इन अफवाहों को खारिज किया है। भारत में लॉकडाउन के संदेह का जन्म संसद में पीएम के बयान की गलत व्याख्या,अफवाहों के कारण कुछ जगहों पर पैनिक बाइंग की स्थिति उत्पन्न हुई, इंडियन ऑइल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने सफाई दी हैसरकार का स्पष्ट संदेश है क़ि देश में पर्याप्त फ्यूल स्टॉक मौजूद है। लॉकडाउन और फ्यूल क्राइसिस की खबरें पूरी तरह भ्रामक है सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी से सतर्क रहने की अपील की गई है। 27 मार्च 2026 को भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीयमंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही लॉकडाउन की खबरों को पूरी तरह गलत और हानिकारक बताया है। लोग घबराएं नहीं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें, क्योंकि ईंधन और जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है।

साथियों बात अगर हम सोशल मीडिया और अफवाहों का तंत्रः डर का नया स्रोत इसको समझने की करें तो आज के डिजिटल युग में सूचना जितनी तेजी से फैलती है,उतनी ही तेजी से भ्रम और अफवाहें भी फैलती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऊर्जा लॉकडाउन और देशव्यापी बंदी जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे,जिससे आम लोगों में डर का माहौल बन गया।पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगीं,गैस सिलेंडर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद अचानक बढ़ गई।यह स्थिति बताती है कि संकट केवल वास्तविक नहीं होता, बल्कि उसकी धारणा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। जब लोग यह मान लेते हैं कि कोई बड़ा संकट आने वाला है,तो उनका व्यवहार भी उसी अनुसार बदल जाता है,चाहे वास्तविक स्थिति उतनी गंभीर न हो। साथियों बात अगर हम भारत की रणनीतिः संतुलन और स्थिरता को समझने की करें तो भारत ने पिछले कुछवर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर बढ़ता जोर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण ये सभी कदम भारत को इस प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।सरकार का वर्तमान फोकस स्पष्ट है:आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना,कीमतों को नियंत्रित रखना,जनता में घबराहट को रोकना,जनता की भूमिका-संयम और जागरूकता- किसी भी संकट के दौरान सरकार की नीतियों के साथ-साथ जनता का व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि लोग अफवाहों पर विश्वास करके अनावश्यक खरीददारी करते हैं, तो इससे कृत्रिम संकट उत्पन्न हो सकता है।इसलिए यह आवश्यक है कि लोग केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें।

साथियों बात अगर हम राजनीतिक बयानबाज़ी और उसक़े प्रभाव को समझने की करें तो,इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक बयानबाज़ी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगा सकती है और लोगों को घरों में कैद कर सकती है।उन्होंने 2021 के लॉकडाउन और चुनावों का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी।हालांकि, ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से दिए जाते हैं,लेकिन इनका असर आमजनता पर गहरा पड़ता है। जब एक वरिष्ठ नेता इस तरह की आशंका व्यक्त करता है, तो लोगों के मन में अनिश्चितता और भय और अधिक बढ़ जाता है। साथियों बात अगर हम पीएम के संसद में बयान और उसक़े गलत अर्थ को समझने की करें तो,सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि पीएम ने संसद में अपने संबोधन के दौरान लॉकडाउन का संकेत दिया था।लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने केवल कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए यह कहा था कि हमें हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई।यह घटना यह दर्शाती है कि किस तरह आधी-अधूरी जानकारी या संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किए गए बयान बड़े पैमाने पर सटीक रूप से गलतफहमी पैदा कर सकते हैं।

2026 में वामिका गब्बी का धमाका

सात फिल्मों से करेंगी दर्शकों का मनोरंजन

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'भूत-बंगला से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहीं वामिका गब्बी के लिए साल 2026 बेहद खास साबित होने जा रहा है। अभिनेत्री इस साल एक-दो नहीं, बल्कि कुल सात फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। खास बात यह है कि उनकी ये फिल्में अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में होंगी, जिससे उनका बहुआयामी अभिनय दर्शकों को देखने को मिलेगा। वामिका गब्बी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म 'भूत-बंगला से साल की शुरुआत करेंगी। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं और यह हॉरर-कॉमेडी जॉनर में बनी है। फिल्म में डर और हंसी का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों को एक अलग अनुभव मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा वामिका करीब चार साल बाद मलयालम सिनेमा में भी वापसी करने जा रही हैं। वह फिल्म 'टिकी टाका में आसिफ अली के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म पहले 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसके मई 2026 में रिलीज होने की संभावना है। फिल्म का निर्देशन रोहित वीएस कर रहे हैं, जो एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तमिल सिनेमा में भी वामिका अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। वह फैंटेसी फिल्म 'जिनी में जयम रवि और कल्याणी प्रियदर्शन के साथ नजर आएंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अलग और दिलचस्प बताया जा रहा है, जो दर्शकों को आकर्षित करेगा। हिंदी सिनेमा में भी वामिका की कई फिल्में लाइनअप में हैं। 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जबकि 'पति पत्नी और वो दो में रिश्तों की नोक-झोंक और हास्य का तड़का देखने को मिलेगा। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और ये जल्द ही रिलीज के लिए तैयार हैं। पंजाबी सिनेमा में भी वामिका 'किकली के जरिए एक्शन अवतार में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ मंदी तखर और जोबनप्रीत मुख्य भूमिकाओं में होंगे। इसके अलावा वह एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जी-2 में भी नजर आएंगी, जो साल के मध्य तक रिलीज हो सकती है। कुल मिलाकर, 2026 वामिका गब्बी के करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जहां वह अलग-अलग भाषाओं और किरदारों के जरिए अपनी अभिनय क्षमता का दमदार प्रदर्शन करती नजर आएंगी।

विलेन से लेकर संवेदनशील किरदारों तक : प्रकाश राज का शानदार फिल्मी सफर

'आली रे आली, आता तुमची बारी आलीयह डायलॉग सुनते ही जयकांत शिकरे का खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है, जिसे प्रकाश राज ने फिल्म सिंघम में जीवंत किया था। अपने किरदार को और प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने बॉडी लैंग्वेज में बदलाव करते हुए गुस्से को हाथों की खास हरकतों से जाहिर किया, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। यही समर्पण उन्हें हिंदी और दक्षिण भारतीय निमा का दमदार विलेन बनाता है। प्रकाश राज का असली नाम प्रकाश राय है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना सरनेम बदलकर 'राज कर लिया, जो आज उनकी पहचान बन चुका है। फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के कारण उनके लिए शुरुआत आसान नहीं थी। काम की तलाश में वे एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक पैदल जाते थे। फिल्मों और टीवी में आने से पहले वे थिएटर कलाकार थे, जहां उन्हें महीने के लगभग 300 रुपये मिलते थे। थिएटर के बाद उन्हें दक्षिण भारतीय टीवी सीरियल्स में काम मिलने लगा। कन्नड़ भाषी होने के बावजूद उन्होंने तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषाओं में भी काम किया। शुरुआती दिनों में भाषा उनके लिए चुनौती रही, लेकिन उन्होंने मेहनत से सभी भाषाएं सीखीं और आज वे खुद अपनी फिल्मों की डबिंग करते हैं। तमिल सिनेमा में उन्हें पहचान डूएट से मिली, जहां बड़े कलाकारों के बीच भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। इसके बाद घिल्ली, पोकिरी और ओक्काडू जैसी फिल्मों में उनके खलनायक किरदारों ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री वान्टेड से हुई, जिसके बाद सिंघम रिटर्न, दबंग 2 और हीरोपंती जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी विलेन की छवि को और मजबूत किया। हालांकि, उन्होंने खुद को सिर्फ नकारात्मक किरदारों तक सीमित नहीं रखा। अभिउम नानम, आकाशमंथा और धोंनी जैसी फिल्मों में उन्होंने एक संवेदनशील पिता का किरदार निभाकर दर्शकों को भावुक कर दिया। अपने अभिनय से हर भावना को पर्दे पर उतारने वाले प्रकाश राज आज भी इंडस्ट्री के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में गिने जाते हैं।

संघर्ष से स्टारडम तक : अर्चना पूरन सिंह की सफलता की प्रेरक कहानी

अर्चना पूरन सिंह आज भले ही टीवी और मनोरंजन जगत की एक जानी-मानी हस्ती हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। 'कुछ-कुछ होता है में मिसेज ब्रिगेंजा के किरदार से लेकर द कपिल शर्मा शो में जज के रूप में उनकी हंसी ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई है।

देहरादून में जन्मीं अर्चना ने कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अर्चना ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। फिल्मों में आने से पहले वह कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी थीं। करमचंद जैसे लोकप्रिय शो में उन्होंने डबल रोल निभाकर अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। उस समय छोटे पर्दे पर डबल रोल करना एक बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अर्चना ने इसे बेहद सहजता से निभाया। हालांकि, यह शो ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इससे उन्हें पहचान जरूर मिली। फिल्मी दुनिया में कदम रखना उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण रहा। साल 1987 में उन्हें पहली फिल्म जलवा का ऑफर मिला, लेकिन इसके लिए उन्हें कई अन्य मॉडल्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाए जाने पर वह घर से दूर थीं और उस समय उन्होंने 100 रुपये खर्च कर टैक्सी से स्टूडियो पहुंचने का फैसला किया। उस दौर में यह रकम काफी बड़ी मानी जाती थी। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया और आखिरकार उनका चयन हो गया, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक सीन में उनके सह-कलाकार साइरस ब्रोचा उन्हें गले लगाने में झिझक रहे थे, क्योंकि वे उस समय काफी शर्मीले थे। यह सीन फिल्म के लिए बेहद जरूरी था। ऐसे में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें समझाया कि अभिनय में झिझक की कोई जगह नहीं होती। उनके समझाने के बाद ही वह सीन पूरा किया जा सका। अर्चना पूरन सिंह का करियर इस बात का उदाहरण है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास कितना जरूरी होता है। टीवी से लेकर फिल्मों और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तक उन्होंने हर माध्यम में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज वह न सिर्फ अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा और बेबाक अंदाज के लिए भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।

सान्या मल्होत्रा की 'सुंदर पूनम की शूटिंग शुरू, रोमांस और सस्पेंस से भरी कहानी को लेकर बढ़ा उत्साह

बॉलीवुड में इन दिनों मजबूत कंटेंट और नई कहानियों वाली फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दर्शक अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ऐसी फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से भी जोड़ सकें। इसी ट्रेंड के बीच सान्या मल्होत्रा की आगामी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'सुंदर पूनम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, जिससे फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया है। सान्या मल्होत्रा ने इस खास मौके को अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया। उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले पारंपरिक मुहूर्त पूजा की और उसकी झलक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। तस्वीरों में फिल्म का क्लैपबोर्ड नजर आता है, वहीं कुछ कैंडिड फोटोज में वह अपने सह-कलाकारों के साथ दिखाई दे रही हैं। एक वीडियो में सान्या पूजा के दौरान आरती करती नजर आती हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि 'सुंदर पूनम की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन पुलकित कर रहे हैं, जबकि इसमें सान्या के साथ आदित्य रावल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म प्राइम वीडियो के 2026 के प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिससे इसकी पहुंच वैश्विक दर्शकों तक होने की उम्मीद है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया था, जिसमें सान्या मल्होत्रा दुल्हन के रूप में नजर आईं। वीडियो में उनका किरदार पूनम एक रहस्यमयी स्थिति में दिखाई देता है, जहां उसका फोन लगातार बजता रहता है और 'सुंदर व 'राजू नाम से कॉल आते हैं। अंत में एक खबर सुनाई देती है कि कश्मीर में एक शादीशुदा जोड़ा लापता हो गया है, जो कहानी में सस्पेंस को और गहरा बना देता है। फिल्म की कहानी रोमांस, क्राइम और थ्रिलर का मिश्रण बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक वास्तविक घटना से प्रेरित है और इसमें एक नवविवाहित जोड़े की कहानी दिखाई जाएगी, जो हनीमून के लिए कश्मीर जाता है। इसी दौरान उनके अचानक गायब होने की खबर सामने आती है, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। खास तौर पर दुल्हन पूनम के किरदार से जुड़ा रहस्य कहानी को और दिलचस्प बनाता है। कुल मिलाकर 'सुंदर पूनम एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आ रही है, जो दर्शकों को भावनात्मक जुड़ाव के साथ-साथ रहस्य और रोमांच का अनुभव भी देगी।

इन्फ्लुएंसर्स नहीं ले सकते एक्टर्स की जगह : हितेन तेजवानी

डिजिटल युग में मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने फिल्मों व वेब शोज के कंटेंट को भी नई दिशा दी है। अब कई बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे चेहरे नजर आने लगे हैं, जो पहले केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सीमित थे। इस बदलाव के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इन्फ्लुएंसर्स की बढ़ती मौजूदगी से प्रोफेशनल और प्रशिक्षित कलाकारों के अवसर कम हो जाएंगे। इसी विषय पर टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता हितेन तेजवानी ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। हितेन तेजवानी का मानना है कि इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स के बीच तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियां अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी किरदार को निभाने के लिए मजबूत अभिनय कौशल की आवश्यकता होती है और ऐसे में मेकर्स हमेशा उसी कलाकार को चुनते हैं, जो उस भूमिका के साथ न्याय कर सके। उनके अनुसार, एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसे सीखने, समझने और अनुभव के साथ निखारने की जरूरत होती है, और यह हर किसी के लिए आसान नहीं होती। उन्होंने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कार्य करने के तरीके पर भी प्रकाश डाला। हितेन के मुताबिक, शूटिंग के दौरान समय का काफी दबाव रहता है, इसलिए निर्माताओं को ऐसे कलाकारों की जरूरत होती है जो कम समय में बेहतरीन प्रदर्शन दे सकें। उन्होंने कहा कि खासतौर पर उन प्रोजेक्ट्स में, जिनकी कहानी गहरी और प्रभावशाली होती है, वहां अनुभवी और प्रतिभाशाली कलाकारों को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे किरदार में गहराई और विश्वसनीयता ला सकते हैं। हितेन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रोजेक्ट में काम करना या न करना कलाकार का व्यक्तिगत निर्णय होता है। हर अभिनेता अपनी पसंद, स्क्रिप्ट और भूमिका के आधार पर काम चुनता है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि इन्फ्लुएंसर्स पूरी तरह से एक्टर्स के अवसर छीन लेंगे। उनके अनुसार, इंडस्ट्री में सभी के लिए जगह है और हर वर्ग का अपना महत्व है। उन्होंने यह भी माना कि किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई लोकप्रिय चेहरा जुड़ता है, तो उससे उसकी पहुंच बढ़ती है और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। हालांकि, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कहानी को मजबूती देने के लिए अनुभवी और कुशल कलाकार मौजूद हों। थिएटर और एक्टिंग बैकग्राउंड से आने वाले कलाकारों की सराहना करते हुए हितेन तेजवानी ने कहा कि ऐसे कलाकार अपने अनुभव और गहरी समझ के जरिए किरदार को जीवंत बना देते हैं। उनकी मेहनत और कला कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाती है, जो दर्शकों के दिल तक पहुंचती है।

न्यूज ब्रीफ

धोनी आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाहर हुए

चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों से बाहर हो गये हैं। धोनी के बाहर होने से टूर्नामेंट शुरु होने से पहले ही सीएसके की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। इसका कारण है कि धोनी टीम का हौंसला बढ़ाने के साथ ही उसे मार्गदर्शन भी देते रहे हैं। वह पिंडली में आये खिंचाव के कारण अभी रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनका शुरुआत से खेलना संभव नहीं है। सीएसके का मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें टीम को उनकी कमी खलेगी। धोनी के बाहर होने से साफ है कि अब सैमसन उनकी जगह पर विकेटकीपर रहेंगे। सीएसके अपना पहला मुकाबला सोमवार को राजस्थान रॉयल्स ये खेलेगी। उसे पहले दो सप्ताह में पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स से भी खेलना है। धोनी के नहीं होने से विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अब विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इस सत्र से पहले सैमसन को सीएसके ने ट्रेड डील के जरिये हासिल किया था।

आईपीएल इतिहास में युवराज सिंह का अनोखा रिकॉर्ड, एक ही सीजन में दो हैट्रिक का कमाल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में भी उन्होंने कई बार मैच का रुख बदला है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या इंडियन प्रीमियर लीग, जब भी उन्हें गेंद थमाई गई, उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। ऐसा ही एक ऐतिहासिक कारनामा उन्होंने आईपीएल 2009 में किया, जो आज तक कोई दोहरा नहीं सका है। आईपीएल का दूसरा सीजन 2009 में खेला गया था, जिसमें युवराज सिंह पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) का हिस्सा थे। उस सीजन में उन्होंने बल्ले से भी अहम योगदान दिया और 2 अर्धशतकों की मदद से 340 रन बनाए। हालांकि, असली इतिहास उन्होंने अपनी गेंदबाजी से रचा। युवराज सिंह ने उस सीजन में दो अलग-अलग मैचों में हैट्रिक लेने का अद्भुत कारनामा किया। उनकी पहली हैट्रिक रॉयल चेलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ आई, जहां उन्होंने लगातार गेंदों पर रॉबिन उथप्पा, जैक्स कैलिस और मार्क बाउचर को आउट कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने डेक्कन चार्ज के खिलाफ मुकाबले में दूसरी हैट्रिक ली।

वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक : जलालुद्दीन ने रचा था इतिहास

नई दिल्ली। साल 1971 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और तब से इस फॉर्मेट में कई बदलाव देखने को मिले हैं। समय के साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में नए-नए कीर्तिमान बने, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहते हैं। ऐसा ही एक खास रिकॉर्ड है हैट्रिक लेने का, जो किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट हासिल करता है, तो उसे हैट्रिक कहा जाता है। यह न सिर्फ मैच का रुख बदलने वाला पल होता है, बल्कि गेंदबाज के करियर का भी एक यादगार क्षण बन जाता है। वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड जलालुद्दीन के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने साल 1982 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। उस मुकाबले में जलालुद्दीन ने लगातार तीन गेंदों पर रॉड मार्श, ब्रूस यार्डली और ज्योफ लॉसन को आउट कर सनसनी मचा दी थी। उनकी इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने वह मैच 59 रन से जीत लिया था। जलालुद्दीन की यह हैट्रिक वनडे क्रिकेट के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद से अब तक इस फॉर्मेट में कई गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार दशकों में वनडे क्रिकेट में 50 से ज्यादा बार हैट्रिक देखने को मिल चुकी है, लेकिन पहली हैट्रिक का गौरव हमेशा जलालुद्दीन के नाम ही रहेगा।

एमआई विरुद्ध केकेआर वानखेड़े में हाईवोल्टेज टक्कर

आंकड़ों में मुंबई भारी लेकिन हालिया फॉर्म में कोलकाता आगे

नई दिल्ली ● एजेंसी

आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत के साथ ही रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है। टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की उम्मीद है, जहां मुंबई इंडियस और कोलकाता नाइट रायडर आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 29 मार्च को मुंबई कें वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पाण्डया के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स की कमान अजिक्य रहाणे संभाल रहे हैं। दोनों कप्तानों के लिए यह मुकाबला खास होगा, क्योंकि शुरुआती जीत टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है। अगर दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां मुंबई इंडियंस का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। अब तक दोनों के बीच कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें मुंबई ने 24 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता को सिर्फ 11 मैचों में जीत मिली है। शुरुआती सीजन में मुंबई ने लगातार दबदबा बनाए रखा और 2008-09 में सभी मुकाबले अपने नाम किए। हालांकि, 2012 के बाद तस्वीर थोड़ी बदली। 2014 और 2015 में केकेआर ने मुंबई पर बढ़त बनाई और चार में से तीन मैच जीते। इसके बाद 2016 से 2018 तक मुंबई ने फिर से पूरी तरह वापसी करते हुए लगातार सात मुकाबले जीत लिए। लेकिन हालिया सीजनों पर नजर डालें तो कोलकाता ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले चार सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए छह मुकाबलों में से चार में केकेआर ने जीत दर्ज की है, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। खिताब की बात करें तो मुंबई इंडियंस अब तक पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है और छठे खिताब की तलाश में है। टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब अपने नाम किए थे। वहीं, कोलकाता नाइटराइडर्स तीन बार (2012, 2014 और 2024) चैंपियन बन चुकी है और इस सीजन में अपने प्रदर्शन को और मजबूत करना चाहेगी। कुल मिलाकर यह मुकाबला आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म के बीच दिलचस्प जंग होने वाला है। जहां एक ओर इतिहास मुंबई के पक्ष में है, वहीं हालिया प्रदर्शन के आधार पर कोलकाता को हल्के में नहीं आंका जा सकता। क्रिकेट फैंस के लिए यह मैच एक रोमांचक शुरुआत का वादा करता है।

मुंबई इंडियंस की टीम

रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), राज बावा, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सैंटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमरा, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.

कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम

अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरुन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा.

धूल भरे गांव से आईपीएल तक

मंगेश यादव की कहानी, संघर्ष, सपनों और पिता के त्याग की मिसाल

नई दिल्ली ● एजेंसी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव बोरगांव से निकलकर रॉयल चेलेंजर बेंगलुरु तक पहुंचने वाले मंगेश यादव का सफर सिर्फ 5.2 करोड़ रुपये की बोली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक परिवार के संघर्ष, त्याग और अटूट विश्वास की कहानी है। यह कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी उस इंसान को नहीं रोक सकतीं, जिसके पास प्रतिभा और उसे तराशने वाला सही मार्गदर्शक हो। मंगेश के पिता रामावध यादव ट्रक ड्राइवर रहे हैं, जिनकी जिंदगी लगातार सफर, अनिश्चित आय और कठिन हालातों से भरी रही। दिन-रात मेहनत करने के बावजूद उनके मन में एक ही सपना था अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य देना। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने मंगेश की ट्रेनिंग कभी नहीं रुकने दी, चाहे इसके लिए उन्हें उधार ही क्यों न लेना पड़ा हो। कई रातें उन्होंने यह सोचते हुए बिताईं कि अगली फीस कहां से आएगी, लेकिन बेटे के हौसले को टूटने नहीं दिया। मंगेश की प्रतिभा को पहली पहचान तब मिली जब उनके चाचा ने उन्हें दिल्ली भेजने की सलाह दी। पिता ने जैसे-तैसे 24,000 रुपये जुटाए और उन्हें कोच फूलंचंद शर्मा के पास भेज दिया। दिल्ली में शुरुआती संघर्ष बेहद कठिन रहा न रहने की जगह, न खाने का ठिकाना। लेकिन कोच ने उनकी प्रतिभा ो पहचानते हुए उन्हें सहारा दिया और रहने-खाने की व्यवस्था करवाई। यही वह मोड़ था, जिसने मंगेश के करियर को नई दिशा दी। हालांकि, इस सफर में एक दौर ऐसा भी आया जब मंगेश अनुशासन से भटक गए। तब उनके कोच ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें घर लौटने तक की चेतावनी दे दी। यह झटका मंगेश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने खुद को संभाला और फिर पूरी मेहनत के साथ क्रिकेट में जुट गए। डीडीसीए लीग से लेकर यूपी अंडर-19 कैंप तक उन्होंने लगातार मेहनत की, हालांकि कई बार चयन न होने की निराशा भी झेलनी पड़ी। उनकी मेहनत का असली फल 'मध्य प्रदेश टी20 लीग में मिला, जहां उन्होंने 6 मैचों में 14 विकेट लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्हें आरसीबी के ट्रायल के लिए बुलाया गया, जहां दिनेश कार्तिक ने उनकी काबिलियत को परखा। मंगेश ने हर स्थिति में खुद को साबित किया और अंततः उन्हें 5.2 करोड़ रुपये में टीम ने अपने साथ जोड़ लिया। आज मंगेश की सफलता उनके पिता के संघर्ष का सम्मान है। जो लोग कभी उनके सपनों का मजाक उड़ाते थे, वही अब उनकी सराहना कर रहे हैं। मंगेश के लिए सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं, बल्कि अपने पिता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान है, जिसने इस पूरे सफर को सार्थक बना दिया।

आईपीएल 2026 में कोहली पड़ेंगे भारी, आकाश चोपड़ा ने धोनी-रोहित पर भी रखी अपनी राय

नई दिल्ली ● एजेंसी

आकाश चोपड़ा का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कोहली की फिटनेस और निरंतरता को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया है। आकाश चोपड़ा ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा कि विराट कोहली की फिटनेस उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। उन्होंने याद दिलाया कि आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खिताब दिलाने में कोहली की भूमिका बेहद अहम रही थी। कोहली ने उस सीजन में 15 मैचों में 657 रन बनाए थे और आठ अर्धशतक जड़े थे, जो उनकी शानदार फॉर्म का प्रमाण है। चोपड़ा के मुताबिक, कोहली जब एक बार लय पकड़ लेते हैं तो लगातार रन बनाते हैं। साथ ही, सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलने से उन्हें पारी की शुरुआत से ही समय मिलता है, जिससे वह खुद को बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यही बात रोहित शर्मा पर भी लागू होती है, लेकिन मौजूदा समय में कोहली की निरंतरता उन्हें बढ़त दिलाती है। वहीं एमएस धोनी को लेकर चोपड़ा ने कहा कि उनके लिए आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। धोनी की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है और लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद सीधे आईपीएल में उतरना आसान नहीं होता। इसके अलावा, निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्हें बहुत कम गेंदें खेलने का मौका मिलता है और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी निभानी होती है, जिससे उनका काम और कठिन हो जाता है। रोहित शर्मा को लेकर चोपड़ा ने कहा कि उनसे एक बार फिर आक्रामक शुरुआत की उम्मीद रहेगी। मुंबई इंडियंस के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए रोहित की भूमिका पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत देने की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब टीम में क्विंटन डी कॉक, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे बल्लेबाज मौजूद हों, तो शुरुआती ओवरों का अधिकतम फायदा उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर, आकाश चोपड़ा का मानना है कि आईपीएल 2026 में जहां अनुभव और आक्रामकता अहम भूमिका निभाएंगे, वहीं फिटनेस और निरंतरता के दम पर विराट कोहली बाकी दिग्गजों से आगे निकल सकते हैं।

गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत से शुरुआत

हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, कोहली-पडिक्कल की फिफ्टी

बेंगलुरु ● एजेंसी

2025 के आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने शनिवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 201 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत का लक्ष्य 15.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 69, देवदत्त पडिक्कल ने 61 और रजत पाटीदार ने 31 रन बनाए। गेंदबाजी में जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3 विकेट लिए। सनराइजर्स हैदराबादसे कप्तान ईशान किशन ने 80, अनिकेत वर्मा ने 43 और हेनरिक क्लासन ने 31 रन बनाए। हर्ष दुबे और जयदेव उनादकट को 1-1 विकेट मिला। डेविड पेन ने 2 विकेट लिए। रविवार को 19वें सीजन का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7.30 बजे से शुरू होगा।

बॉटम | बीसीसीआई ने जारी किया घरेलू सीजन 2026-27 का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया समेत चार टीमों की मेजबानी करेगा भारत

नई दिल्ली ● एजेंसी

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय टीम के घरेलू सीजन 2026-27 का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस सीजन में भारत कुल 17 शहरों में 22 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगा और आस्ट्रेलिया समेत चार टीमों की मेजबानी करेगा। टीम इंडिया का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप 2026 के बाद खिलाड़ी सीधे इंडियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) 2026 में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत 28 मार्च से होगी। आईपीएल के बाद जून में भारतीय टीम एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगी, जबकि जुलाई में उसे इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां पांच टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद घरेलू सीजन का आगाज 27 सितंबर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से होगा। इस दौरे में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। वनडे मुकाबले त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में होंगे, जबकि टी20 मैच लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी। इसके बाद दिसंबर 2026 में श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आएगी। इस दौरान तीन वनडे और तीन टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। वनडे मैच दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में होंगे, जबकि टी20 सीरीज राजकोट, कटक और पुणे में आयोजित की जाएगी। नए साल 2027 की शुरुआत जिम्बाब्वे के दौरे से होगी। जिम्बाब्वे की टीम जनवरी में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत आएगी, जिसके मुकाबले कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेले जाएंगे। यह सीरीज 3 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगी। सीजन का समापन प्रतिष्ठित बार्डर-गावस्कर ट्राफी के साथ होगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी 2027 से नागपुर में शुरू होगा, जबकि बाकी मैच चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। कुल मिलाकर, यह घरेलू सीजन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम और व्यस्त रहने वाला है, जिसमें फैंस को देश के अलग-अलग शहरों में हाई-वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे।

न्यूज ब्रीफ

एसआईआर के विरोध में ममता का धरना प्रदर्शन जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी है। ममता रातभर धरना स्थल पर मौजूद रहीं। ममता ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेसिव रिविजिन (एसआईआर) में मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में 6 मार्च दोपहर 2 बजे से कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरु किया है। सीएम ममता ने समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर में मतदाता सूची से वोटर्स के नाम हटाना बंगाल को बांटने के इरादे से किया गया है। हमारी सरकार ने बजट में दो योजनाओं की घोषणा की थी। एक है बंगालर युवा साथी और दूसरी है भूमिहीन खेत मजदूर। दोनों योजनाएं अप्रैल से शुरु होनी थीं, लेकिन हमारी सरकार ने इन्हें आज से शुरु करने का फैसला किया है। वे बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा राज्य कई योजनाएं लाने में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई हैं। अब आपको 21 दिन पहले गैस बुक करानी होगी, तब अगर आपके घर में एलपीजी खत्म हो जाए, तब आप 21 दिन क्या करेंगे? खाएंगे क्या?

नीतीश ने राजभवन पहुंचकर की राज्यपाल से मुलाकात

पटना। बिहार की राजनीति में जारी हलचल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात औपचारिक विदाई प्रोटोकॉल के तहत मानी जा रही है। राजभवन से पहले जनता दल (यू) के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इन बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में संभावित प्रवेश से पहले सीएम के बेटे नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पटना में संजय झा के आवास पर जेडीयू के करीब 24 विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ और युवा विधायक मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति और संगठन की स्थिति पर चर्चा की गई।

गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर लखनऊ रवाना हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ा। अपने ही देश में, अपने ही वोट से चुनी गई सरकार के सामने, अपनी ही गौ-माता को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बातें काशी में लखनऊ रवाना होने से पहले कही। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को 'गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभाÓ का नाम दिया। वे 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले है। यहां हजारों संतों की मौजूदगी में सभा करने वाले है। इसमें केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की जाएगी। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था- गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। वरना मैं आंदोलन करुंगा। शंकराचार्य काशी से जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर होकर 5 दिन बाद लखनऊ पहुंचने वाले है। यात्रा में 20 से अधिक गाड़ियां हैं। 500 से अधिक श्रद्धालु साथ हैं। इस दौरान लोगों को पोस्टर बांटे गए। इनमें लिखा है। जिंदा हिंदू लखनऊ चलें। इससे पहले, शंकराचार्य सुबह 8.30 बजे मठ से निकलकर गौशाला पहुंचे। गाय की पूजा की। फिर पालकी पर सवार हुए। मठ से 300 मीटर दूर स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर पहुंचे। यहां 11 बटुकों ने उनका स्वागत किया। फिर पूजा-अर्चना कर संकट मोचन मंदिर पहुंचे।

ईरानी युद्धपोत को डुबाने को लेकर अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी ने किया झूठा दावा

अमेरिका के साथ संधि किसी भी संघर्ष में शामिल होने हमें मजबूर नहीं कर सकती : भारत

नई दिल्ली ● एजेंसी

श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री तट के पास हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस डेना को परमाणु पनडुब्बी से टॉरपीडो हमला करके डुबोया है, उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच हुई एक दशक पुरानी संधि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की अहमियत बढ़ गई है। दरअसल, बिना संधि का जिक्र किए अमेरिकी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने इसकी ओर इशारा करते हुए एक झूठा दावा किया है, जिसके बाद इसे समझना जरूरी हो गया है। भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह संधि किसी भी संघर्ष में शामिल होने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकती। भारत और अमेरिका ने 29 अगस्त, 2016 को लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक तरह से बुनियादी सैन्य समझौता है, जिसके तहत एक-दूसरे को ईंधन भरने, सप्लाई और मरम्मत के लिए मिलिट्री

सुविधाओं के आपसी इस्तेमाल की सुविधा मिलती है। अमेरिका की कई देशों के साथ ऐसी संधि है। यह संबंधित देशों और अमेरिका के बीच आपसी सैन्य सहयोग के लिए की गई है। यह संधि मूल रूप से दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों के लिए ईंधन और मरम्मत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। भारत-अमेरिका लंबे समय से साझा युद्धाभ्यास करते हैं, जिसमें इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा से रही है। इस संधि के जरिए सिर्फ इस प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया गया है और दोनों ओर से भुगतान और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं के उपयोग के लिए नोडल प्वाइंट तय किए गए हैं। आपस में लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अलावा यह संधि मुख्य तौर पर चार क्षेत्रों को कवर करती है। इसमें पोर्ट कॉल, संयुक्त युद्धाभ्यास, साझा मिलिट्री ट्रेनिंग और मानवीय सहायता के साथ-साथ आपात स्थिति में मदद करना शामिल है। हालांकि, किसी भी स्थिति में इस संधि पर अमल दोनों तरफ से आपसी सहमति से ही हो सकता है, जो मामले पर निर्भर करता है। इस समझौते में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। भारत की धरती पर अमेरिकी सैनिक या संपत्ति का कोई अड्डा नहीं हो सकता है। यह पूरी तरह से एक लॉजिस्टिक समझौता है। भारत जरूरत पडऩे पर अमेरिकी सैन्य सुविधाओं का जरुरत के मुताबिक लॉजिस्टिक इस्तेमाल कर सकता है और यही अमेरिका भी भारत में कर सकता है। यह समझौता भारत को किसी भी संघर्ष में शामिल होने का दबाव नहीं डाल सकता और न ही इसकी वजह से भारत स्वतः किसी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने को मजबूर है। दरअसल, अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने एक अमेरिकी मीडिया चैनल पर झूठा दावा किया कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय नौ सैनिक अड्डे का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो हमले में ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस डेना को भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर हिंद महासागर में डुबोया है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारतीय समुद्र तट से करीब 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल मील तक फैला है। मतलब, श्रीलंका के दक्षिणी तट से दूर जिस जगह पर अमेरिकी हमला हुआ, वह भारतीय समुद्री सीमा से बहुत दूर है। आईआरआईएस डेना में 130 ईरानी नाविक सवार थे, जिनमें अमेरिकी हमले में 87 लोगों की मौत हो गई और 32 को श्रीलंकाई नेवी ने रेस्क्यू किया। आईआरआईएस डेना से आपात संदेश मिलने के बाद भारतीय नौ सेना भी सर्च ऑर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई थी।

भारत ने ईरान के आईरिस लावन को दी शरण, 183 चालक दल के सदस्यों को कोच्चि में ठहराया

श्रीलंका ने भी एक अन्य ईरानी युद्धपोत आईरिस बुशहर में खराबी आने के बाद दी शरण

नई दिल्ली ● एजेंसी

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब भारत के समुद्री पड़ोस तक पहुंच गया है। श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने के बाद, भारत ने ईरान के एक दूसरे युद्धपोत आईरिस लावन को कोच्चि बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दे दी है। इस कदम को भारत द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद जटिल बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तनाव की शुरुआत बुधवार को हुई जब श्रीलंका के तट से करीब 19 समुद्री मील दूर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट आईरिस डेना पर टॉरपीडो से हमला कर उसे डुबो दिया था। इस भीषण हमले में 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि यह पहली बार है जब अमेरिका-ईरान संघर्ष भारत के इतने करीब पहुंच गया है। ईरानी युद्धपोत आईरिस लावन एक उभयचर युद्धपोत है। यह पिछले महीने भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने आया था। अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने 28 फरवरी को भारत से संपर्क कर तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए युद्धपोत को कोच्चि में डॉक करने का अनुरोध किया था। भारत ने 1 मार्च को इसकी मंजूरी दी और बुधवार को यह जहाज कोच्चि पहुंचा। जहाज के 183 चालक दल के सदस्यों को वर्तमान में कोच्चि में नौसैनिकों के साथ ठहराया गया है। भारत की तरह श्रीलंका ने भी एक अन्य ईरानी युद्धपोत आईरिस बुशहर को अपने यहा शरण दी है। इंजन में खराबी

के बाद इसके 208 सदस्यों को एक नौसैनिक कैंप में ठहराया गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक ने इसे एक मानवीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत संकट में फंसे जहाज की मदद करना उनका कर्तव्य है। भारत के लिए यह स्थिति किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ ईरान के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है। देश के भीतर विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने भारत के रणनीतिक बैकयार्ड में ईरानी जहाज के डूबने पर भारत की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से बंद करने की धमकियों के बीच भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50फीसदी इसी मार्ग से मंगाता है।

राष्ट्रपति के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा व्यक्त नाराजगी एवं पीड़ा के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जो भी लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, वे इस घटना से बेहद आहत और निराश हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त दर्द और पीड़ा ने देशवासियों के मन को गहरी ठेस पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले में सारी सीमाएं पार कर दी हैं और राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संथाली संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इतनी लापरवाही से लिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इजरायल ने फिर दी सफाई कहा- पीएम मोदी के दौरे से ईरान पर हमले का कोई संबंध नहीं था

नई दिल्ली ● एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल के दौरे पर थे और उनके लौटने के ठीक दो दिन बाद यह हमला हुआ। हमले की इस सटीक टाइमिंग को लेकर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विवाद को बढ़ता देख अब इजरायल ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि इस सैन्य कार्रवाई का पीएम मोदी के दौरे से कोई संबंध नहीं था।

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने शुक्रवार को रायसीना डायलॉग में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी को इस हमले के बारे में कोई पूर्व जानकारी या ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बेहद मजबूत और रणनीतिक हैं, लेकिन हम उन्हें इस बारे में सूचित नहीं कर सके क्योंकि सैन्य कार्रवाई का अंतिम निर्णय उनके जाने के बाद, शनिवार तड़के लिया गया था। इजरायल ने स्पष्ट किया कि जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह विफल हो गई, तब यह कड़ा कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। विदेश मंत्री के अनुसार, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, नई बैलिस्टिक मिसाइलें और हिजबुल्लाह व हमास जैसे संगठनों को मिल रहा समर्थन इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। उन्होंने संकेत दिया कि अब ईरान में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। मध्य पूर्व में मार्च की शुरुआत एक भीषण सैन्य संघर्ष के साथ हुई है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल क्षमताओं और मिलिशिया नेटवर्क पर बड़ा हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत और तेहरान व इस्फहान जैसे शहरों में हुई भारी तबाही ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया है, लेकिन इस तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजरायल यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। इजरायल द्वारा बार-बार दी जा रही इस सफाई के पीछे एक बड़ी कूटनीतिक वजह है। भारत हमेशा से मध्य पूर्व में शांति और संतुलन का पक्षधर रहा है। इजरायल नहीं चाहता कि उसके रणनीतिक साझेदार भारत पर ईरान के खिलाफ किसी सैन्य साजिश में शामिल होने या उसे मौन समर्थन देने का आरोप लगे।

केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक जहां-जहां घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन-चुनकर बाहर खदेड़ा जाएगा : शाह

हरिद्वार ● एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड सरकार के '4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शनिवार को शामिल हुए। इस मौके पर जनसभा को संबोधित कर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि को संवार रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने फिर कहा कि केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहां-जहां घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन-चुनकर भारत से बाहर किया जाएगा।

इसके पहले केंद्रीय मंत्री शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने ई-0 एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की और 1129.91 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिसके बाद सीएए के तहत 3 पाकिस्तानी और 1 अफगानिस्तानी शरणार्थी को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। कार्यक्रम स्थल पर अलग-अलग जिलों से भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और साधु-संत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बीजेपी के चाणक्य शाह ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में 10 हजार से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगा रही है, जबकि भाजपा सरकार अवैध अतिक्रमण और घुसपैठ के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि आने वाले समय में इसका सबसे बड़ा फायदा देवभूमि उत्तराखंड को होगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहां-जहां घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन-चुनकर भारत से बाहर खदेड़ा जाएगा। शाह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री धामी की सरकार चार साल पूरे कर रही है और भाजपा सरकार के भी नौ साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस सरकार के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था।

बॉटम

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजन-अर्चन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को किया संबोधित

कृष्ण की कृपा से अयोध्या जैसे भव्य मंदिर का निर्माण ब्रज में भी होगा : योगी आदित्यनाथ

मथुरा ● एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए और ब्रज क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनका पूरा कार्यक्रम आध्यात्मिक माहौल में डूबा नजर आया। मुख्यमंत्री ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लेते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी और अधिकारियों को तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि भगवान कृष्ण की कृपा रही तो जिस तरह अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है, उसी प्रकार यहां भी आगे का कार्यक्रम होगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर केशवदेव मंदिर, योगमाया मंदिर और गर्भगृह में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए और विधिवत पूजन-अर्चन कर श्रद्धा निवेदित की। ब्रज की पावन धरा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रज भूमि का कण-कण ऊर्जा और

भक्ति से भरा है। प्रभु श्रीकृष्ण के चरणों में शीश नवाकर मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान का आशीर्वाद प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर बना रहे। उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने कहा मथुरा की धरती का हर कण भगवान कृष्ण की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। यहां की हवा और वातावरण में राधारानी और कृष्ण कन्हैया की भक्ति रची-बसी है, जो हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि यदि भगवान कृष्ण की कृपा रही तो जिस तरह अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है, उसी प्रकार यहां भी आगे का कार्यक्रम होगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जोरदार जयकारे लगाए और पूरा परिसर 'जय श्रीकृष्ण के नारों से गूंज उठा। इससे पहले वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मथुरा-वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है। योगी ने खास तौर पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि ब्रज क्षेत्र देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए यहां का विकास भी उसी स्तर पर होना चाहिए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक- नितिन श्रीवास द्वारा पंकज प्रीटर्स एड पेकिंजिंग, ए-16, एल्फा पार्क, सांवेर रोड,एल्फा इंदौर (मध्यप्रदेश) से मुद्रित 1054-एल, यूनियन बैंक, स्कीम नं. 114 इंदौर से प्रकाशित।
संपादक- नितिन श्रीवास, आर.एन.आई. नम्बर - एमपीएचआईएन/2003002 (सभी विवादों का न्यायलय क्षेत्र इंदौर रहेगा)